सत्यमेव जयते

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

Digital India
Power To Empower

राज्य प्रालेख

सितम्बर-2025

NIC

Digital India
Power To Empower

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.0	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश की प्रमुख गतिविधियां - जनवरी 2023 से	3
1.1	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश परियोजनायों द्वारा जीते गए पुरस्कार	19
2.0	हिमाचल प्रदेश में एन.आई.सी. नेटवर्क (निकनेट) (एन.के.एन., वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, इंटरनेट नोड्स, कनेक्टिविटी, वी. सैट.)	22
3.0	मुख्य कार्यालयों में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र द्वारा सहायता	23
4.0	मोबाइल एप्लीकेशन (G2C G2E G2B G2G, एंड्रॉयड, विंडोज़ और एप्पल प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप्स)	24
4.1	जिला प्रशासन मोबाइल चुनौती 2021 (राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र जिलों द्वारा विकसित ऐप्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी)	31
5.0	राज्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर परियोजना (प्रत्येक परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी)	34
6.0	राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्टवेयर परियोजनाएं	501
7.0	विकास/कार्यान्वयन के तहत प्रमुख परियोजनाएं	57
8.0	आयोजित प्रशिक्षण	61
9.0	प्रमुख गतिविधियों की योजना	62

1.0 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हि. प्र. की प्रमुख गतिविधियां (जनवरी 2023 से)

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
1	वर्तमान मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित बैठक हेतु एन आई सी द्वारा गग्गल हवाई अड्डे पर पी एम ओ की स्थापना की गई। (09-सितंबर-2025)	
2	हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा विभाग के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए गृह रक्षा स्वयंसेवक प्रबंधन प्रणाली पर डेमो-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। (16-सितंबर-2025)	
3	श्री सुखविंदर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रही मानसून स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। (29-अगस्त-2025)	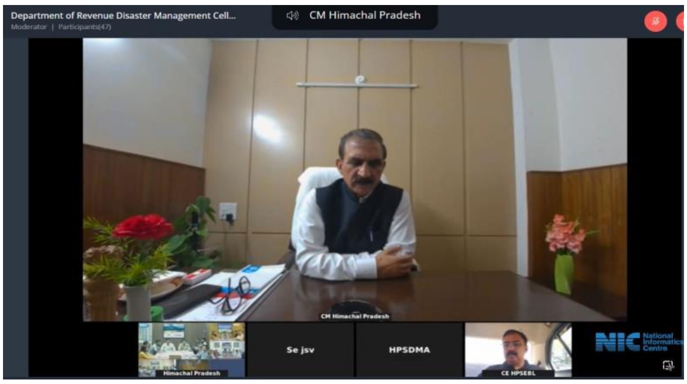

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
4	श्री के. के. पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एच पी एस डी एम एफ (राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष) एम आई एस के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन पीएसी बैठक की। (06 अगस्त 2025)	
5.	माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह ने भूमि पंजीकरण को जनता और अधिकारियों के लिए आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु 'माई डीड' (एनजीडीआरएस) और सरलीकृत जमाबंदी एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। (11-जुलाई-2025)	
6.	राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र, जोन-II सम्मेलन हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन, धर्मशाला में आयोजित किया गया है। (30 जून एवं 01 जुलाई 2025)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2025 का आयोजन किया। इस दौरान आसन, ध्यान आदि योग गतिविधियों का आयोजन किया गया। (21 जून, 2025)	
8	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान विभाग (NeGD), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला में UX4G कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश, कोषागार और हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। (17 और 18 जून 2025)	
9	श्री सुखविंदर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने एकल उपयोग पॉलिथीन (एस यू पी) एस डब्ल्यू और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ताकि अधिकारी प्रतिबंधित एकल-उपयोग पॉलिथीन वस्तुओं के उपयोग के लिए चालान कर सकें। (05-जून-2025)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
10	हिमाचल प्रदेश के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के प्रधान सलाहकार (डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं शासन) श्री गोकुल बुटेल की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सभी दूरस्थ प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सेवा प्रदान की गई। कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया। (20 मई, 2025)	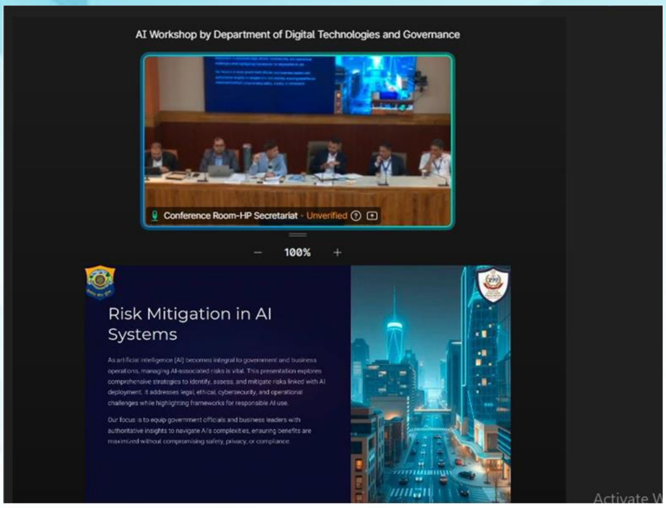
11	माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सी.पी.आर.आई. शिमला में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। (26 अप्रैल, 2025)	
12	पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। (25 अप्रैल, 2025)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
13	माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री सुखविंदर सिंह ने राज्य के सभी विभागों में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आधारित बैठक ली है। (24 अप्रैल, 2025)	
14	माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री सुखविंदर सिंह ने नेवा (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन) का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया। (17 मार्च, 2025)	
15	माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भागलपुर बिहार में आयोजित 19वें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस्त विमोचन समारोह में केवीके सुंदरनगर से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। एनआईसी एचपी ने के वी के सुंदरनगर में वर्चुअल माध्यम से सेवाएं प्रदान कीं। (24 फरवरी, 2025)	
16	इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदाराना उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एन आई सी हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य मुख्यालय और जिलों में "एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए" थीम के तहत सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कर्मचारियों, छात्रों और	

	पी आर आई/यू एल बी के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। (11 फरवरी, 2025)	
17	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1-31 जनवरी, 2025) के दौरान, राज्य परिवहन विभाग और एनआईसी द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी हितधारक विभागों और एजेंसियों के लिए हिपा में iRAD/eDAR परियोजना पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। (18 जनवरी, 2025)	
18	माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की 27 ग्राम पंचायतों के 1106 मालिकों को वर्चुअल माध्यम से संपत्ति कार्ड वितरित किए। (18 जनवरी, 2025)	

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>गतिविधि/पुरस्कार</th><th>फोटो</th></tr>
<tr><td>19</td><td>माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' विषय पर उत्तरी क्षेत्र सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

(11 जनवरी, 2025)</td><td>
</td></tr>
<tr><td>20</td><td>श्री कुलदीप सिंह पठानिया, माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा, श्री सुखविंदर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और श्री जय राम ठाकुर, माननीय विपक्ष के नेता द्वारा NeVA (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन) का उद्घाटन।

(18-दिसंबर-2024)</td><td> </td></tr>
<tr><td>21</td><td>एन आई सी हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप के लिए प्रतिष्ठित एम-गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 (15वें राष्ट्रीय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2024) से सम्मानित किया गया है।

(13-दिसंबर-2024)</td><td>
</td></tr>
<tr><td>22</td><td>एन आई सी हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र शिमला में डीडीजी-सह-राज्य समन्वयक एनआईसी हिमाचल प्रदेश श्री आई.पी.एस. सेठी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय डीआईओ कार्यशाला का आयोजन किया गया।
(11 और 12-दिसंबर-2024)</td><td>
</td></tr>
</table>

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
23	एन आई सी हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में शिमला में एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित ई-टूल्स (कोलैबफाइल्स, ई-ताल और गवर्नमेंट इन सिक्योर इंट्रानेट) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। (10-दिसंबर-2024)	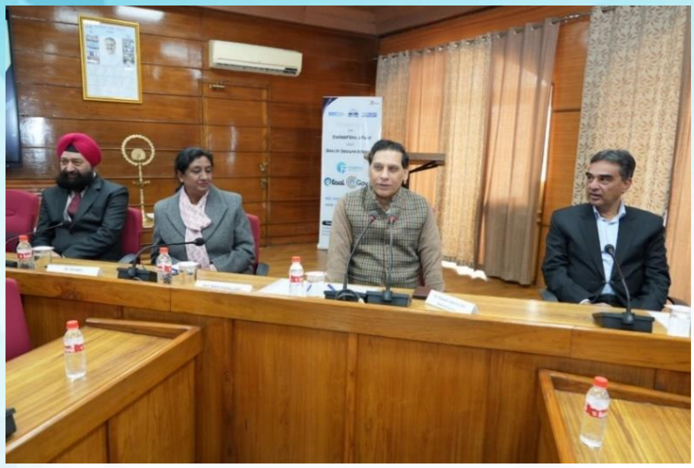
24	एच.पी. एस डी ए म एफ (राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) एम आई एस के सभी हितधारकों के लिए डेमो-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। (20-नवम्बर-2024)	
25	एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW - 2024) मनाया गया। VAW-2024 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। (28 अक्टूबर से 03 नवंबर-2024)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
26	सी आई पी एस (सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र) पुरस्कार 2024 के लिए प्रस्तुतियाँ। एच.पी. रेरा, सहयोग एम.आई.एस., एच.पी. बड़े बांध सुरक्षा विश्लेषण एम.आई.एस., स्कूल सुरक्षा एम.आई.एस. और PSC सॉफ्ट परियोजनाओं के लिए प्रस्तुतियाँ दी गईं। (23, 24 और 28-अक्टूबर-2024)	
27	ई-एच आर एम एस की प्रतिकृति के लिए मेघालय सरकार के अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय डेमो-सह-प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। (15 और 16-अक्टूबर-2024)	
28	एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिता, कविता, निबंध लेखन आदि विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। (14 से 28 सितंबर-2024)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
29	एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शिकायत अपीलीय समिति MIS और हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए स्कूल सुरक्षा एमआईएस/मोबाइल ऐप के लिए GEMS ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2024 26 जुलाई 2024	
30	योग अभ्यास के लाभों के बारे में अपने अधिकारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एनआईसी हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया (21-जून-2024)	
31	मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश ने लोकसभा मतदान कर्मचारियों के आम चुनाव के लिए 10 मई 2024 को धर्मशाला जिला कांगड़ा में इलेक्शन क्विज़ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। (10-मई-2024)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
32	हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के श्री अंकुश ठाकुर (स्टेट रोलआउट प्रबंधक) और विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को आई आर ए डी परियोजना मे बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया (25-अप्रैल-2024)	
33	मतदान कर्तव्यों के लिए विभागीय/निगम/बोर्ड कर्मचारियों के लिए सभी जिलों में नेक्स्टजेन डी आई एस ई सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण आयोजित किए गए और सभी जिलों में सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री का काम शुरू कर दिया गया है। (मार्च-2024)	
34	जिला स्तर के प्रमुखों के लिए वेबसाइटों/एप्लिकेशन और मोबाइल ऐप की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल और स्पीति जिलों में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। (3 से 29-फरवरी-2024)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
35	जिला सिरमौर में जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों के लिए वेबसाइटों/एप्लिकेशन और मोबाइल ऐप की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। (13-10-2023)	
36	हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खु, द्वारा स्कूल आपदा प्रबंधन योजना मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस का शुभारंभ किया। (13-10-2023)	
37	संसदीय राजभाषा समिति धर्मशाला का दौरा किया और एनआईसी एवं अन्य केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा किए जा रहे हिंदी राजभाषा के कार्यों का निरीक्षण किया। (3 से 5-10-2023)	
38	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत ई-भर्ती के रूप में PSCSoFT प्रतिकृति के लिए लोक सेवा आयोग, मॉरीशस सरकार के अधिकारियों को डेमो-सह-प्रशिक्षण। (1 से 15 सितंबर 2023)	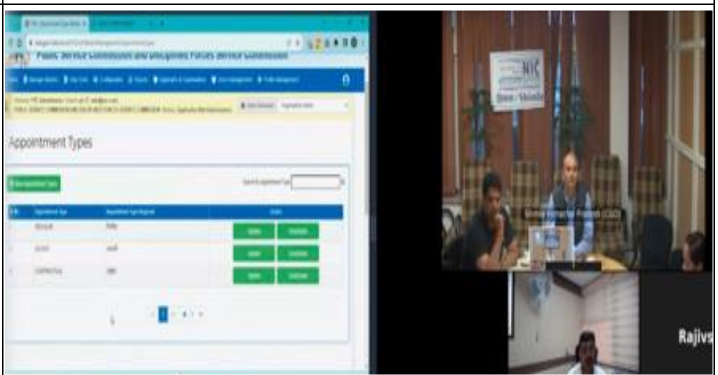

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
39	एनआईसी हिमाचल प्रदेश में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया और राजभाषा दिशानिर्देशों के अनुसार आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। (14-28 सितंबर 2023)	
40	श्री ए.एन. मिश्रा, डी.डी.जी. एवं एन.आई.सी. हि.प्र. के राज्य समन्वयक का हिमाचल प्रदेश का दौरा तथा 8-9 जून 2023 को शिमला में मुख्य सचिव, हि.प्र. और सचिव (आई.टी.) के साथ बैठक, एवं एन.आई.सी. सोलन, राष्ट्रपति भवन मशोबरा का दौरा। (7 से 9 जून-2023)	
41	माननीय विधायक श्री राजेश धर्माणी द्वारा घुमारवीं (बिलासपुर) विधान सभा क्षेत्र के तीन सरकारी स्कूलों के स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया गया। (22-जून-2023)	
42	श्री अमरनाथ मिश्रा, उपमहानिदेशक और एन.आई.सी. हि.प्र. राज्य समन्वयक ने वी.सी. के माध्यम से सभी हि.प्र. अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और प्रस्तुतियों को देखा। (26-अप्रैल-2023)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
43	जल शक्ति विभाग के लिए एन आई सी एच पी द्वारा विकसित एम आई एस सॉफ्टवेयर के लिए सी एस आई ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार। (25-मार्च-2023)	
44	सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस प्रशंसा पुरस्कार हि.प्र. रेरा एम.आई.एस. और हि.प्र. लोक सेवा आयोग के लिए विकसित पी.एस.सी. सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के लिए दिया गया। (25-मार्च-2023)	
45	सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस मान्यता पुरस्कार हि.प्र. बड़े बांध सुरक्षा विश्लेषण और हि.प्र. कृषि खरीद पोर्टल के लिए दिया गया। (25 मार्च-2023)	
46	GePNIC (ई-टेंडर / ई-प्रोक्योरमेंट) के प्रसार के लिए राज्यों द्वारा सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश समन्वयक श्री पृथ्वी राज नेगी, उप निदेशक (आई.टी.) को मन्यता पुरस्कार। (27-मार्च-2023)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
47	आई.टी. और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने एन.आई.सी. हि.प्र. द्वारा विकसित शिकायत अपीलीय मंच (जी.ए.सी.) का शुभारंभ किया। (28-फ़रवरी-2023	
48	हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डे-बोर्डिंग स्कूलों और गौ सदनों के संबंध में उपायुक्तों के साथ बैठक की। (28-जनवरी-2023)	
49	भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा, एन.आई.सी. कांगड़ा द्वारा विकसित ई-कैच मोबाइल एप्लिकेशन के लिए श्री निपुण जिंदल, आई.ए.एस. डी.सी. कांगड़ा को राज्य विधानसभा चुनाव 2022 को सर्वश्रेष्ठ आई.सी.टी. इंटरवेंशन पुरस्कार दिया गया। (25-जनवरी-2023)	

क्र.	गतिविधि/पुरस्कार	फोटो
50	श्री अभिषेक जैन, आई.ए.एस. सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार, 17-18 जनवरी 2023 को शिमला में जिला सूचना-विज्ञान अधिकारियों की कार्यशाला के दौरान राज्य / जिलों के एन.आई.सी. अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए। (18-जनवरी-2023)	
51	हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूमि डूबने के संबंध में उपायुक्तों के साथ बैठक की। (16-जनवरी-2023)	

1.1 सम्मान/पुरस्कार

पुरस्कार का नाम	वर्ष	परियोजना का नाम मान्यता और विवरण	सम्मेलन /स्थान
एम-गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2024	2024	स्कूल सुरक्षा मोबाइल ऐप	गुवाहाटी, 13-दिसंबर-2024
जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया	2024	स्कूल सुरक्षा मोबाइल ऐप और वेब एम आई एस	नई दिल्ली, 26-जुलाई-2024
जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया	2024	MeitY-शिकायत अपीलीय समिति एम आई एस	नई दिल्ली, 26-जुलाई-2024
GePNIC का प्रसार	2023	सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सम्मान - श्री पृथ्वी राज	नई दिल्ली, 27-मार्च-2023
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार	2023	जल शक्ति विभाग का वर्क्स प्रबंध सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर	दिल्ली, 25-मार्च-2023
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस प्रशंसा पुरस्कार	2023	हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण प्रबंध सूचना प्रणाली	दिल्ली, 25-मार्च-2023
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस प्रशंसा पुरस्कार	2023	परिवर्तन के लिए लोक सेवा आयोग सॉफ्टवेयर	दिल्ली, 25-मार्च-2023
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस मान्यता पुरस्कार	2023	हि. प्र. बड़े बांध सुरक्षा विश्लेषण प्रबंध सूचना प्रणाली	दिल्ली, 25-मार्च-2023
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस मान्यता पुरस्कार	2023	हिमाचल प्रदेश कृषि उपज खरीद पोर्टल	दिल्ली, 25-मार्च-2023
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार	2022	ऑक्सीकेयर (ऑक्सीजन आपूर्ति निगरानी सूचना प्रणाली)	प्रयागराज, 23-अप्रैल-2022
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार	2022	आरटी -पी सी आर (कोविड-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली)	प्रयागराज, 23-अप्रैल-2022
स्टेट मोबाइल चुनौती	2021	एन.आई.सी. हि.प्र. द्वारा ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल एप्लिकेशन	वर्चुअल समारोह, 12-अक्टूबर-2021
जिला प्रशासन मोबाइल स्वर्ण चुनौती पुरस्कार	2021	एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश राज्य को समग्र प्रदर्शन हेतु	वर्चुअल समारोह, 28-मई-2021
	2021	शिमला द्वारा ई-अनुमतियाँ ऐप	

	2021	एन.आई.सी. सोलन द्वारा ई-कल्याण ऐप	
जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2021	2021	कोविड-19/ आर.टी.-पी.सी.आर. ऐपस	जेम्स ऑफ डिजिटल - वर्चुअल आयोजन
स्कॉच सिल्वर	2021	कोविड-19/ आर.टी.-पी.सी.आर. ऐपस	स्कॉच वर्चुअल आयोजन
सी.एस.आई. - एस.आई.जी. ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21	2021	कोविड-19/ आर.टी.-पी.सी.आर. ऐपस / रति मोबाइल ऐप्स	लखनऊ, यूपी में सी.एस.आई. सम्मेलन, 12-फरवरी-2021
डिजिटल इंडिया पुरस्कार- महामारी में नवाचार के लिए स्वर्ण	2020	कोविड-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली https://covid19cc.nic.in	भारत के माननीय राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित किया, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 30-दिसंबर-2020
सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता और मान्यता पुरस्कार	2020	हिम प्रगति को-ऑपरेशन प्रबंध सूचना प्रणाली	भुवनेश्वर, ओडिशा में सी.एस.आई. सम्मेलन 17-जनवरी-2020
जेम्स ऑफ़ डिजिटल इंडिया	2019	मध्याह्न भोजन स्वचालित रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली	जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया सम्मेलन, नई दिल्ली
डिजिटल इंडिया 2018 स्वर्ण - वेब रत्न	2019	राज्य पोर्टल https://himachal.nic.in	डिजिटल इंडिया पुरस्कार- फरवरी 2019, नई दिल्ली
स्वच्छता पुरस्कार और हिंदी पुरस्कार	2019	स्वच्छता अभियान और हिंदी प्रयोग में दूसरा रैंक	विविड-मीट, नई दिल्ली TOLIC अवार्ड्स, शिमला
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण	2018	मानव संपदा-राज्यों में तेजी से प्रयोग के लिए	21वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, हैदराबाद
	2018	ऑनलाइन रोहतांग पास परमिट जारी करने की प्रणाली (एन.जी.टी.)	21वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, हैदराबाद
प्रौद्योगिकी सभा-उद्यम सॉफ़्टवेयर	2018	मध्याह्न भोजन स्वचालित रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली	आई.ई. प्रौद्योगिकी सभा, इंदौर
विशिष्टता के लिए ओपन ग्रुप पुरस्कार	2018	लोक सेवा आयोग एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क	ओपन ग्रुप कॉन्फ्रेंस, बेंगलुरु
जेम्स ऑफ़ डिजिटल इंडिया	2018	मानव संपदा	जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया कांफ्रेंस, नई दिल्ली
सी.एस.आई. निहिलेंट ई-गवर्नेंस	2017	मध्याह्न भोजन स्वचालित रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली	सी.एस.आई. राष्ट्रीय सम्मेलन, कोलकाता
सी.एस.आई. निहिलेंट ई-गवर्नेंस	2017	मानव संपदा - जीविका का पुरस्कार	सी.एस.आई. राष्ट्रीय सम्मेलन, कोलकाता
डिजिटल इंडिया पुरस्कार स्वर्ण	2016	मध्याह्न भोजन मोबाइल एप्लीकेशन	डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2016, नई दिल्ली

श्रेष्ठ पेपर-एन.सी.ई.जी. संग्रह	2016	भविष्य के लिए साइबर सुरक्षा नीति	20वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, विजाग
स्कोच स्मार्ट गवर्नेंस पुरस्कार	2016	सारथ 4.0-ड्राइविंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन	स्कोच समिट, हैदराबाद
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण	2015	एकीकृत ऑनलाइन होटल आरक्षण प्रणाली सॉफ्टवेयर	19वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, नागपुर
डिजिटल इंडिया पुरस्कार	2015	डिजिटल इंडिया अभियान के लिए देश का दूसरा सबसे अच्छा राज्य	नेशनल डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2015, नई दिल्ली
सी.एस.आई. निहिलेंट ई-गवर्नेंस	2015	एकीकृत भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण	सी.एस.आई. राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली
सी.एस.आई. निहिलेंट ई-गवर्नेंस	2015	हिमकोश-एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली	सी.एस.आई. राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली
स्कोच स्मार्ट गवर्नेंस पुरस्कार	2015	ई-एच.आर.एम.एस. मानव संपदा	स्कोच समिट, नई दिल्ली

पिछले वर्षों में, **9 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 3 वेब रत्न पुरस्कार** और कई अन्य सम्मान/पुरस्कार एन.आई.सी. हि.प्र. ई-गवर्नेंस परियोजनाओं (सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ई-पेंशन, भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, कानून व्यवस्था, लोकमोत्र, ई-विकास, HIMRIS, REFNIC, eGazette) को प्रदान किए गए हैं। **उपरोक्त के अलावा**, वर्ष 2012 में 2 सी.एस.आई. निहिलेंट ई-गवर्नेंस अवार्ड्स (ई-एच.आर.एम.एस.), 2013 में आई.सी.जे.एस. और वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान एन.आई.सी. हि.प्र. परियोजनाओं के लिए मेरिट के 30 से अधिक स्कोच ऑर्डर और 1 राज्य सिविल सेवा पुरस्कार (मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त किया गया है। वर्ष 2013 और 2014 में हिम-भूमि और जेल-वार्ता (कैदी रिश्तेदार वी.सी. आधारित बातचीत) के लिए 2 मंथन ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

2.0 एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश में निकनेट सेवाएं

(एन.के.एन., वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, इंटरनेट नोड्स, कनेक्टिविटी, वी-सैट)

नेटवर्क एक नजर में

- हिमाचल प्रदेश में छोटा क्लाउड आरम्भ हो गया है ।
- भारत संचार निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलटेल द्वारा 3*10 जी.बी. की कोर कनेक्टिविटी प्रदान की गई।
- संस्थानों और एन.आई.सी. जिलों के लिए 1 जी./100/34 एम.बी.पी.एस. की हाई स्पीड कनेक्टिविटी।
- हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लगभग 1500 नोड्स का लैन।
- एन.आई.सी. हि.प्र. ने कई मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए हि.प्र. सचिवालय में वाई-फाई नेटवर्क स्थापित किया गया है। वर्तमान में 1900 से अधिक वाई-फाई खाते बनाए गए हैं।
- राज्य में सरकारी अधिकारियों को 9000 से अधिक ई-मेल खाते प्रदान किए गए।
- एन.आई.सी. के दूरस्थ जिलों (किन्नौर एवं लाहौल और स्पीति) और हिमाचल प्रदेश के 4 जनजातीय उप-मंडलों में वी-सैट आधारित कनेक्टिविटी दी गयी है।

NICNET को केंद्र सरकार के कार्यालयों तक विस्तारित किया गया है, और एन.के.एन. हिमाचल प्रदेश में प्रमुख संस्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क उच्च बैंडविड्थ, कम विलंबता नेटवर्क है। परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक, चिकित्सा, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी नेटवर्क को भी जोड़ना है एन.आई.सी. ने एन.के.एन. परियोजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 24 संस्थानों को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की है, सभी महत्वपूर्ण शैक्षिक, चिकित्सा, अनुसंधान संस्थान एन.के.एन. से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यालय भी हिमस्वान के माध्यम से एन.के.एन. से जुड़े हुए हैं। एन.आई.सी. ने हिमाचल प्रदेश के 4 जनजातीय उपमंडलों और हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ जिलों के लिए बैकअप लिंक के रूप में वी.सैट कनेक्टिविटी भी प्रदान की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवाएं मुख्य मंत्री कार्यालय, राज भवन, विधानसभा, एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स और जिलों के सभी एन.आई.सी. केंद्रों में उपलब्ध हैं। एन.आई.सी. ने पूह, भरमौर, काजा और पांगी के 4 जनजातीय उप-मंडलों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की है। एन.आई.सी. द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परियोजनाओं के साथ एकीकृत है। सभी परियोजनाओं को एकीकृत किया गया है, और किसी भी एन.आई.सी. आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली से ब्लॉक स्तर तक वी.सी. संभव है। सभी एन.आई.सी. स्टूडियो फुल हाई डेफिनिशन वी.सी. सुविधा प्रदान करते हैं।

आयोजित किये गये वी.सी. सत्र

जनवरी 2018 से 30 सितम्बर 2025 के बीच 18,089 वी.सी. सत्र आयोजित किए गए।

3.0 मुख्य कार्यालयों में एन.आई.सी. सहायता

संगठन का नाम		
राज्यपाल सचिवालय	आवश्यकता के आधार पर सहायता	वी.सी., वाई-फाई, द्विभाषी वेबसाइट, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर (एच.डी.टी.एस.) समर्थन, नियमित जनशक्ति तैनात नहीं है
हि.प्र. विधानसभा	वेतन, गेटपास, वेबसाइट जैसी विभिन्न गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण में आवश्यकतानुसार आई.टी. सहायता प्रदान करना	हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्पूर्ण कामकाज के लिए राष्ट्रीय मानक कागज रहित समाधान के रूप में 18 दिसंबर, 2024 को ई-विधान एप्लीकेशन को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एन.आई.सी. हि.प्र. स्टेट सेंटर	• नेटवर्क संचालन केंद्र • सॉफ्टवेयर विकास दल • डाटा सेंटर / वी.सी. स्टूडियो	इंटरनेट/ ईमेल/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकास, सभी जिलों, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों को नेटवर्क सहायता
मुख्य मंत्री कार्यालय	मुख्यमंत्री संदर्भ निगरानी, मुख्यमंत्री राहत प्रबंध सूचना प्रणाली आदि	मुख्यमंत्री कार्यालय की आवश्यकताएं
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों की सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करना और इंटरनेट से इन्हें ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में जोड़ना है	हाई स्पीड इंटरनेट, वेबसाइट का विकास/ रखरखाव, वाद सूची/ मामले की स्थिति/ आदेशों की प्रतियों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और विभिन्न कार्यों के लिए कार्यान्वित
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स	राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं ई-एच.आर.एम.एस. और मध्यांतर आहार - और केंद्र सरकार के कार्यालयों को सहायता एन.के.एन. / निक-नेट पी.ओ.पी., राज्य मिनी डाटा सेंटर के द्वारा दी जाती हैं	नेटवर्क, सॉफ्टवेयर विकास, होस्टिंग, एल.एल. और एन.के.एन. कनेक्टिविटी
12 उपायुक्त कार्यालय	वी.सी. स्टूडियो, लैन, आई.सी.टी. सपोर्ट, एन.के.एन. - स्वान कनेक्टिविटी, स्थानीय सॉफ्टवेयर	उपायुक्त कार्यालयों और जिले के अन्य राज्य कार्यालयों को भी आई.टी. सहायता, ब्लॉक/ तहसील/ सब-डिवीजन स्तर पर आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी सहायता
हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान	हिमाचल प्रदेश में जागरूकता और विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए आई.सी.टी. प्रशिक्षण प्रदान करना। भारत के एन आई सी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।	परीक्षा प्रसंस्करण प्रणाली, हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सरकारी अधिकारियों को आई.सी.टी. प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.0 मोबाइल एप्लिकेशन (एड्रॉइड, एप्पल और विंडोज प्लेटफॉर्म पर ऐप्स जो कि G2C G2E G2B G2G सेवाएं प्रदान करती हैं)

प्रतीक चिन्ह/ आइकन	ऐप का नाम	प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध	सेवा श्रेणी	विवरण
	प्रतिबंधित एस यू पी ई-चालानएचपी		G2G, G2C	प्रतिबंधित एकल उपयोग पॉलिथीन वस्तुओं के उपयोग के उल्लंघन के चालान और प्रबंधन के लिए।
	ई-पेंशन		G2C	सेवानिवृत्त राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए वर्षवार, मासिक पेंशन वितरण विवरण (पी.पी.ओ. संख्या आधारित)
	आई.पी.आर. एच.पी.		G2C	हि.प्र. आई.पी.आर. विभाग द्वारा जारी की जा रही समाचार तस्वीरों सहित नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति
	यू-हिमाचल		G2C	https://himachal.gov.in वेबसाइट पर नियमित रूप से नवीनतम अपडेट की जानकारी दी जा रही है
	ई-गजट		G2C, G2G	ऑनलाइन ई-गजट इंडेक्स, वेब के माध्यम दैनिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएं दिखा रहा है
	ई-सैलरी		G2E	हि.प्र. महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिए गए कर्मचारी के आई.पी. कोड और सामान्य भविष्य निधि पिन के आधार पर वेतन और सामान्य भविष्य निधि / केंद्रीय भविष्य निधि जानकारी।
	ई-एच.आर.एम.एस.		G2E	कर्मचारी कोड के आधार पर कर्मचारी की पूरी ई-सर्विस बुक और वेतन की जानकारी (आई.पी. कोड मैप किए जाने पर)
	ई-ट्रांसफर्स		G2E G2C	आई.ए.एस./एच.ए.एस. आधिकारियों के स्थानांतरण आदेश, विभाग जो ऑनलाइन आदेश जारी करते हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, जल शक्ति विभाग

प्रतीक चिन्ह/ आइकन	ऐप का नाम	प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध	सेवा श्रेणी	विवरण
	ई-चलान		G2B, G2G	डीलर/ वाहन संख्या के आधार पर सरकारी कोषागार में जमा राशि को देखने के लिए बार कोड स्कैनर के माध्यम से सत्यापन की सुविधा
	माय-डायरी		G2C, G2G, G2B	कार्यों के विवरण के साथ ब्लॉक स्तर तक के राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की निर्देशिका और कार्यों के विवरण को जोड़ने की विशेषता
	टूर-मंडी		G2C	सामान्य उपयोग के लिए मंडी पर्यटन ऐप, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित स्थानों, पुलिस स्टेशन, अस्पतालों आदि सहित सभी प्रासंगिक जानकारी देता है
	एक्स.10		G2C	रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने वालों का डेटा उन्हें हरे/नारंगी और लाल रंग में उनकी वैधता अवधि के बारे में याद दिलाने के लिए
	एच.पी.वी.सी.		G2G, G2E	हि.प्र. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूची व आरक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है
	एच.पी.फोनस		G2C, G2G, G2B, G2E	हि.प्र. दूरभाष निर्देशिका में नाम, फोन नंबर, विभाग और पदनाम के आधार पर फ्री टेक्स्ट खोज का विकल्प तथा रिवर्स खोज तरीका भी उपलब्ध है
	राज्यसभा डीबेटस		G2C, G2G	राज्य सभा के सभी वाद-विवाद, सदस्यों, सत्र की तिथियों, विषयवार आधार पर खोज के लिए उपलब्ध हैं
	ई-एस.आर.टी.		G2C, G2G	ट्रांसपोर्टर अपने राज्य के विशेष सड़क कर को देख सकते हैं और उसका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, विभागीय अधिकारी वाहन के खिलाफ विशेष सड़क कर बकाया देखने के लिए चेकिंग के दौरान ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं

प्रतीक चिन्ह/ आइकन	ऐप का नाम	प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध	सेवा श्रेणी	विवरण
	मानव समपदा		G2E, G2G	मानव संपदा उत्पाद के पूरक के लिए सामान्य ऐप जिसे कई अन्य राज्यों द्वारा मानक कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में अपनाया गया है
	एम.डी.एम.-मध्याह्न भोजन		G2G, G2C	एन.आई.सी. हि.प्र. द्वारा विकसित और अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए मध्याह्न भोजन स्वचालित रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली उत्पाद के पूरक के लिए एक सामान्य ऐप, यह ऐप मध्याह्न भोजन प्रभारी को दैनिक व मासिक डेटा भेजने में मदद करता है और उच्च अधिकारियों को दैनिक डेटा स्थिति की प्रभावी निगरानी करने में मदद करता है
	ई-समाधान		G2C	ई-समाधान ऐप वेबसाइट का पूरक है, नागरिक ऐप का उपयोग करके नया आवेदन दर्ज कर सकते हैं और सहेजे गए आवेदनों पर की गई नवीनतम कार्रवाई का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं
	एम-हिमभूमि		G2C	उपयोगकर्ता खेवत/खतौनी/खसरा नंबर या मालिक के नाम का उपयोग करके भूमि रिकॉर्ड खोज सकते हैं, इसके अतिरिक्त जमाबंदी और शजरानस्ब उपयोगकर्ता को मोबाइल उपकरण पर प्लॉट मैप की कॉपी भी मिलती है
	ओफरिस		G2B	ऐप फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों की स्थिति की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है, भवन योजना अनुमोदन, कारखाना पंजीकरण, कारखाना नवीनीकरण, कारखाना संशोधन, लाइसेंस की समाप्ति की जानकारी भी उपलब्ध है

प्रतीक चिन्ह/ आइकन	ऐप का नाम	प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध	सेवा श्रेणी	विवरण
	माय.जी.पी.ऍफ़		G2E	इस ऐप का उपयोग करके हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपने पिछले 5 वर्षों के सामान्य भविष्य निधि विवरण को देख सकते हैं और अन्य संबंधित रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं
	ई-अवास		G2G	यह मोबाइल एप्लिकेशन घरों के आवंटन के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए विकसित वेब-एप्लिकेशन का पूरक है
	जनमनरेगा		G2C	यह राष्ट्रीय ऐप मनरेगा संपत्तियों को देखने के लिए और संपत्ति की फीडबैक सबमिट करने हेतु, (संपत्ति निर्देशांक के लिए स्थान की जाँच के साथ)
	एम-बजट-एच.पी.		G2G G2E G2C G2B	राज्य का पूरा बजट ऐप में उपलब्ध है और उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से देख सकता है
	ई-भुगतान		G2G G2E G2C G2B	राज्य सरकार द्वारा किए गए भुगतान को उपयोगकर्ताओं के कई जुड़े हुए बैंक खातों के आधार पर देखा जा सकता है
	शक्ति		G2C G2G	यह एक महिला सुरक्षा सहायता ऐप है जो आपात स्थिति में महिलाओं की मदद करने के लिए पुलिस थानों से जुड़ा हुआ है।
	रोहतांग परमिटस		G2G G2C	इस ऐप द्वारा पर्यटक और टैक्सी ऑपरेटर रोहतांग परमिट की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं
	हिम टी.सी.पी. एरिया चेक		G2C G2B	नागरिक यह देख सकते हैं कि उनका क्षेत्र टाउन कंट्री प्लानिंग क्षेत्र में आता है या नहीं और सूचनाएं देख सकते हैं
	स्त्री-सुरक्षा		G2C G2G	यह कांगड़ा मंडल के पुलिस थानों से जुड़ा एक महिला सुरक्षा सहायता ऐप है

प्रतीक चिन्ह/ आइकन	ऐप का नाम	प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध	सेवा श्रेणी	विवरण
	माय डाक्यूमेंट्स		G2C	नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नवीनीकरण आदि के लिए स्वत: अलर्ट के साथ अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संचित और पुनः प्राप्त कर सकते हैं
	एन.आई.सी.वी.सी.		G2G	एन.आई.सी. वी.सी. ऐप डैशबोर्ड द्वारा, दिन के लिए सभी अनुसूचित वी.सी. सूचीबद्ध करता है, महत्वपूर्ण वी.सी. (यदि कोई हो), मौजूदा माह के दौरान वी.सी. और वर्ष के दौरान वी.सी. को भी सूचीबद्ध करता है ।
	शोर नही		G2C, G2G	शोर नही ऐप को हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की सुविधा के लिए विकसित किया गया है ताकि सुधारात्मक उपायों के लिए अधिकारियों को किसी भी ध्वनि प्रदूषण की घटना की सूचना दी जा सके
	जन समिक्षा		G2C, G2G	राज्य की पंचायतों में निष्पादित जिला स्तरीय कार्यों की गुणवत्ता पर जनता से गुणवत्ता/मात्रा पर आगत प्राप्त करना
	एच.पी. सिविल लिस्ट		G2E, G2C, G2G	राज्य के आई.ए.एस., आई.पी.एस., एच.पी.ए.एस., एच.पी. एस.एस. अधिकारियों की सूची, उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल तरीके से खोज के लिए उपलब्ध है
	राज्यसभा डिबेट्स		G2G,G2C	राज्य सभा की सभी डिबेट्स, विषय, सत्र और सदस्यों के आधार पर खोजने योग्य प्रारूप में उपलब्ध हैं।
	आर.टी.-पी.सी.आर.		G2G	देश में एकत्र किए जा रहे आर.टी.-पी.सी.आर. नमूनों का विवरण एकत्र करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए आर.टी.-पी.सी.आर. मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, इन्हें परीक्षण/ परिणाम अद्यतनीकरण के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है व एप

प्रतीक चिन्ह/ आइकन	ऐप का नाम	प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध	सेवा श्रेणी	विवरण
				के जरिए जुटाई गई से अग्रिम सूचना इन प्रयोगशालाओं तक पहुंचती है
	जल शक्ति वाटर बिल्स		G2C	पूरे राज्य में हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग द्वारा जारी किए गए बिलों के लिए नागरिकों के लिए ऑनलाइन पानी के बिल भुगतान की सुविधा व नागरिक इस इंटरफ़ेस में कई पानी के कनेक्शन मैप कर सकते हैं व नए पानी के कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
	ऑक्सीकेयर		G2G	ऑक्सीजन संकेन्द्रक प्रबंध सूचना प्रणाली ऐप स्वास्थ्य संस्थांनो द्वारा स्वास्थ्य उपकरणों की प्राप्ति/स्थापना और समस्या जानकारी के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रभारी द्वारा उपयोग की जाती है
	ऑक्सीकेयर इंजीनियर		G2G	ऑक्सीकेयर पोर्टल के तहत आपूर्ति किए गए ऑक्सीजन उपकरणों के लिए प्राप्त शिकायतों के प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप, यह ऑक्सीजन उपकरण निर्माताओं के सहायक कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए है, विभिन्न ऑक्सीजन उपकरणों को स्वास्थ्य संस्थांनो में स्थापित किया गया है और ऑक्सीकेयर मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किया गया है। किसी भी ऑक्सीजन उपकरण में कोई समस्या होने पर रिपोर्ट करने के लिए एक ही ऐप का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीकेयर इंजीनियर ऐप के माध्यम से इस उपकरणों को देखने, समाधान करने और स्थिति अपडेट करने का काम किया जाता है

प्रतीक चिन्ह/ आइकन	ऐप का नाम	प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध	सेवा श्रेणी	विवरण
	हिम अतिथि		G2G, G2C	शिमला, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में स्थित सरकारी अतिथि गृहों में आवास की बुकिंग के लिए कर्मचारियों और नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु हिम अतिथि ऐप विकसित किया गया है
	रोहतांग परमिट मॉनिटर		G2G	रोहतांग दर्रे की निगरानी और प्रति-परीक्षण करने के लिए, इस ऐप का इस्तेमाल सरकारी अधिकारी कर सकते हैं, यह परमिट के सुरक्षित क्यू.आर. कोड की पुष्टि करता है जिसे समरूप नहीं किया जा सकता है, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रोहतांग परमिट का गलत इस्तेमाल न हो
	एम-सुविधा		G2C, G2B	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के लिए ऐप विकसित किया गया है, ताकि नागरिकों को अनुकूल तरीके से इलेक्ट्रिकल, प्लंबर, मैकेनिक और चिनाई से संबंधित कार्यों के लिए इन व्यक्तियों से संपर्क करने में मदद मिल सके
	नेचुरल वाटर सोर्सीस		G2G	प्राकृतिक जल स्रोत ऐप राज्य में पानी की कमी को पूरा करने के और मजबूत करने के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों के भौगोलिक कोड, फोटो और अन्य डेटा को अधिकृत करता है, हिमाचल प्रदेश राज्य के 900 अमृत सरोवर स्थलों को अधिकृत करने के लिए इसे अब अपडेट किया गया है
	एलेक्ट्र सर्च हिमाचल		G2C	पी.आर.आई./यू.एल.बी. (राज्य चुनाव आयोग) के मतदाता अपने मतदाता विवरण, मतदान केंद्र विवरण की जांच कर सकते हैं और कई मापदंडों के आधार पर मतदाताओं के नाम खोज सकते हैं

4.1 जिला प्रशासन मोबाइल चुनौती के तहत एन.आई.सी. जिला केंद्रों द्वारा विकसित और लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप

क्र.	जिले का नाम	एप्लिकेशन का नाम	औपचारिक शुभारंभ
1	बिलासपुर	एम्स बिलासपुर	उपायुक्त द्वारा 12-03-2021 को
2	चंबा	चलो चंबा	उपायुक्त द्वारा 15-03-2021 को
3	कांगड़ा	ई-पट्टा	उपायुक्त द्वारा 18-03-2021 को 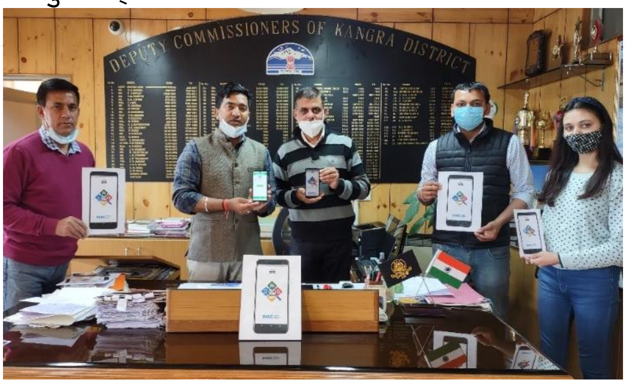

4	मंडी	एम-रोज़नामचा	उपायुक्त द्वारा 15-03-2021 को
5	शिमला	ई-परमीशन	उपायुक्त द्वारा 20-03-2021 को
6	सिरमौर	माय कॉनसीलर	उपायुक्त द्वारा 19-03-2021 को

7	सोलन	ई-कल्याण	उपायुक्त द्वारा 15-03-2021 को

जिला इकाइयों द्वारा विकसित अन्य मोबाइल ऐप

क्र.	जिले का नाम	एप्लिकेशन का नाम	औपचारिक शुभारंभ
1	कांगड़ा (धर्मशाला में)	ई-कैच	ऐप चुनाव व्यय निगरानी को अंकीयकरण करके आम चुनावों के दौरान चुनाव व्यय निगरानी प्रक्रिया में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में विवरण वास्तविक समय के आधार पर लिया जाता है।

5.0 राज्य स्तर पर सॉफ्टवेयर परियोजनाएं (डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन)

सॉफ्टवेयर का नाम	उपयोगकर्ता विभाग/विवरण	कार्यान्वयन की स्थिति
1. ई-कल्याण - कल्याण पेंशन प्रबंध सूचना प्रणाली		
यह सॉफ्टवेयर मनी ऑर्डर के माध्यम से पेंशन के संवितरण को स्वचालित करता है। यह बहीखाता तैयार करने, मृतक/पता नहीं पाए गए पेंशनभोगियों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने आदि के कार्य को भी स्वचालित करता है। यह आवेदन प्राप्त होने के चरण से लेकर पेंशन के वितरण तक पेंशन वितरण (सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार) की प्रणाली को लागू करता है और इससे पेंशनरों को तथा विभाग को अपनी पेंशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की भी मदद मिली है। नया वेब आधारित सॉफ्टवेयर अब विकसित किया गया है और दो जिलों के लिए इसका पायलट परीक्षण किया गया है।		कवरेज: 100% सभी 12 जिलों में लागू लगभग 4.4 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन दी जा रही है (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग- सभी केंद्रीय और राज्य योजनाएं इसके अंतर्गत हैं)
2. AWCMIS (आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंध सूचना प्रणाली)		https://awcmishp.nic.in
आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ने के साथ-साथ इन आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत श्रमिकों/सहायिकाओं के पंजीकरण के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं। आवेदन मासिक मानदेय और अन्य भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्रमय प्रारूप में कई एम.आई.एस. रिपोर्ट उपलब्ध हैं। मानदेय और किराए का ऑनलाइन भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर को राज्य के कोषागारों के साथ एकीकृत किया गया है।		आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले 78 सी.डी.पी.ओ. और लगभग 19000 व्यक्तियों का डेटा उपलब्ध है और एप्लिकेशन का उपयोग आंगनवाड़ी श्रमिकों/ सहायिकाओं के मानदेय और आवास के किराए के भुगतान के लिए किया जा रहा है।
3. ई-गजट - डिजिटल राजपत्र	https://rajpatrahimachal.nic.in	
01-अगस्त-2007 से राजपत्र केवल ऑनलाइन प्रकाशित किए जाते हैं और 2011 से सभी राजपत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब 01-अगस्त-2007 से पहले वर्ष 1953 से 2007 तक हिमाचल प्रदेश के सभी		कवरेज: 100% राजपत्र दैनिक प्रकाशित 1-अगस्त-2007 से लागू

पिछले राजपत्रों को डिजिटल कर दिया गया है और सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के सभी राजपत्र डिजिटल खोज योग्य प्रारूप और ऑनलाइन उपलब्ध हैं।	सभी राजपत्र वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाते हैं। शामिल विभाग: 90
4. हिमभूमि - भू अभिलेख कम्प्यूटरीकरण	
ई-हिमभूमि अद्वितीय सॉफ्टवेयर है क्योंकि यह म्यूटेशन और अन्य लेनदेन के कारण परिवर्तनों को समामेलित करने के बाद अगली जमाबंदी और संबंधित रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है। नागरिक लोकमित्र केंद्र या तहसील केंद्र से अधिकारों का रिकॉर्ड (आर.ओ.आर.) की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोकमित्र केंद्र हिमभूमि वेबसाइट के माध्यम से हस्ताक्षरित आर.ओ.आर. जारी करने के लिए अधिकृत हैं। नागरिक हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://himachal.nic.in/revenue पर जाकर भी आर.ओ.आर. का उपयोग कर सकते हैं। जिन तहसीलों के नक्शों का डिजीटलीकरण एवं सत्यापन किया जा चुका है, उनकी जमाबंदी प्रतियों के साथ प्लॉट मैप्स (मुसावी एवं नवीनतम दोनों) की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आर.ओ.आर. के साथ डिजीटल मानचित्र प्रतियां प्रदान करने के लिए इसे भुनाक्षा सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया गया है। भू अभिलेख को कर्मों के पंजीकरण सॉफ्टवेयर HimRIS के साथ भी एकीकृत किया गया है। जिला, फसल बीमा। भू-स्वामियों का वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल भी सिस्टम के साथ एकीकृत हैं।	तहसीलें ऑनलाइन: सभी 3745 लोकमित्र नागरिक सेवा केंद्रों (2738 लोक मित्र केंद्र उपयोगकर्ताओं ने एक या अधिक आर.ओ.आर. जारी किए हैं) के माध्यम से जमाबंदी, शजरनास्ब वितरण की प्रमाणित प्रति। अब तक लोक मित्र केंद्र /सुगम के माध्यम से कुल 75 लाख+ आर.ओ.आर. प्रतियां जारी की गई हैं, जिससे 17.70 करोड़ रुपये सेवा शुल्क एकत्र हुए हैं।
5. सारथी - ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली	
जनता को स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक मानक समाधान के रूप में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रणाली विकसित की गई है। सॉफ्टवेयर गलत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं देता है।	राज्य के सभी पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण / क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 100% कवरेज, वेब सक्षम सारथी 4.0 लागू किया गया है।
6. वाहन - वाहनों की पंजीकरण सूचना प्रणाली	
वाहन पंजीकरण सॉफ्टवेयर देश भर में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक मानक सॉफ्टवेयर है, जो केंद्रीय राष्ट्रीय रजिस्टर में आंकड़े स्थानांतरित करके देश भर में वाहनों की निगरानी को	राज्य के सभी पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण / क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 100%

सक्षम बनाता है, जो वाहन चोरों के लिए एक निवारक होगा और मालिक का तेजी से पता लगाने/वाहन विवरण में जरूरत के मामले में मदद करेगा।	कवरेज, वेब आधारित वाहन 4.0 लागू किया गया है।
7. परिवहन बेरियर सूचना प्रणाली	
सॉफ्टवेयर को वाहन मालिकों से मानदंडों के अनुसार कर एकत्र करने और विभिन्न वैधानिक और पूछताछ रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ परिवहन बेरियर पर शुल्क संग्रह संरचना को बदलने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है। 10 अंतरराज्यीय परिवहन बैरियरों पर लागू किया गया।	10 अंतरराज्यीय परिवहन बैरियरों पर लागू किया गया।
8. पी.यू.सी. 2.0 (प्रदूषण नियंत्रण में)	
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया जाए और उनके उत्सर्जन की जाँच की जाए, PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) जारी किया जाता है। PUC 2.0 परियोजना, स्वचालित उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों (AETCs) पर वाहन की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य बनाती है और इसमें PUCC जारी करने के लिए मोबाइल डिवाइस की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और जियो-लोकेशन शामिल है।	पी यू सी 2.0 को हिमकोष के साथ एकीकरण के साथ हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है।
9. ई डिटेक्शन	
ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन उन वाहनों की स्वचालित रूप से पहचान करके सड़क सुरक्षा को नया आकार दे रहा है जो या तो ब्लैक लिस्टेड हैं या बिना वैध मोटर वाहन (एमवी) दस्तावेजों जैसे कि टैक्स, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) और परमिट के चल रहे हैं। यह सिस्टम टोल प्लाजा से वाहन डेटा का लाभ उठाता है ताकि एप्लीकेशन द्वारा पहचाने गए डिफॉल्टर वाहनों के लिए ई-चालान जारी किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह वाहन डेटाबेस के साथ क्रॉस-रेफ़रेंसिंग करके नकली नंबर प्लेट वाले नकली वाहनों की पहचान करने में मदद करता है।	हिमाचल प्रदेश में तीन एनएचएआई टोल प्लाजा पर पायलट आधार पर शुरू की गई इस प्रणाली को हिमाचल प्रवेश कर उल्लंघन को भी ई-डिटेक्शन प्रणाली में ई-चेकपोस्ट एप्लीकेशन के माध्यम से एकीकृत किया गया है।
10. नागरिक सेवा केंद्र (सुगम, लोकमित्र, पहल, ई-विकास)	
सुगम केंद्र, अपनी तरह का अनूठा, एक छत के नीचे विभिन्न विभागों के लिए नागरिकों को केंद्रीकृत एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। सेवाओं में विलेख/ वाहन का पंजीकरण, लाइसेंस/ प्रमाण पत्र जारी करना, भुगतान आदि जैसे ऑनलाइन लेनदेन शामिल हैं। यह जिलों के सभी उपायुक्त कार्यालयों में स्थापित है और एक छत के नीचे 50+ से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। **लोकमित्र:** यह ग्रामीण जनता को उनके दरवाजे पर सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करता है, राज्य सरकार ने सभी MeitY प्रायोजित नागरिक सेवा केंद्रों (3243 पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में CSCs) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश द्वारा कार्यान्वित पायलट परियोजना, जो कि पहले हमीरपुर जिले में चलाई गयी	

थी, के आधार पर लोकमित्र केंद्र के रूप में नामित किया है। इसका उद्देश्य लोगों के समय और धन की बचत करना है, जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भौतिक रूप से जाने में खर्च होता है।

पहल-नागरिक सेवा केंद्र: यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाता है और एक ही स्थान पर नागरिकों को बेहतर, मित्रवत, तेज, कुशल सेवाएं प्रदान करता है। सभी जिला मुख्यालयों/ 49 उप-प्रभागों (पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण)/ 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों-एस.टी.ए. में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन सेवाओं के पंजीकरण की पेशकश के लिए सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

11. बजट प्रसंस्करण प्रबंध सूचना प्रणाली

पूरक और नियमित बजट तथा पुनर्विनियोजन एवं बजट दस्तावेजों की वास्तविक समय के आधार पर, राज्य वित्त विभाग के लिए बजट प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजनावार ऑनलाइन योजना बजट प्रस्ताव और अंतिम अनुमान तैयार करने के लिए इसे योजना विभाग और अन्य राज्य विभागों के साथ जोड़ने के लिए सुधार किए गए हैं। सिस्टम अगले 3 वर्षों के लिए योजनावार बजट अनुमान भी तैयार करता है।	सॉफ्टवेयर पिछले कई वर्षों से लागू किया गया है। **बजट सुझाव पोर्टल** को इसके साथ एकीकृत किया गया है।

12. ओल्टिस - एकीकृत ऑनलाइन ट्रेजरी सूचना प्रणाली

i-OLTIS ट्रेजरी संचालन के निर्देशन के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत एप्लिकेशन है। यह बैंकों के लिए भुगतान स्क्रॉल बनाने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन बनाए गए बिलों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है, जिसे बैंक पोर्टल से ही डाउनलोड करते हैं, जिससे लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आती है। यह स्टाम्प वितरण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रबंधन, लेखाकार सामान्य कार्यालय को खाता बनाने और प्रदान करने जैसे अन्य कोषागार संचालन को भी सरल करता है। वास्तविक समय व्यय रिपोर्ट विभागाध्यक्ष/आहरण और संवितरण अधिकारी को आवंटित बजट का कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करती हैं। ऑनलाइन बिल भेजने के लिए विभागीय आवेदन को एकीकृत करने के लिए वेब सेवाओं का विकास किया गया।	कवरेज: 100% 105 कोषागारों में क्रियान्वित किया गया, सभी 16 जिला स्तरीय एवं 89 उप कोषागार कम्प्यूटरीकृत हैं। विभागों के लिए वेब-इंटरफेस, आहरण एवं संवितरण अधिकारी विकसित किया गया है ।

13. ई-वेतन - एकीकृत ऑनलाइन बिल निर्माण और जमा करने की प्रणाली (अब ई-बिल)

एकीकृत वेतन और लेखा प्रणाली कोषागारों में स्थित नामित 52 एकीकृत वेतन और लेखा कार्यालयों में पेरोल प्रसंस्करण के काम को केंद्रीकृत करने के लिए है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कर्मचारियों के मासिक संबंधित परिवर्तनों की प्रक्रिया करते हैं और एकीकृत वेतन और लेखा कार्यालयों को सूचित करते हैं। सभी गैर-वेतन बिलों को भी शामिल करने के लिए आवेदन को बढ़ाया गया है। ऑनलाइन बजट वितरण	कवरेज: 100% एकीकृत वेतन और लेखा के रूप में 52 कोषागार और राज्य सरकार के सभी एकीकृत वेतन और लेखा के लिए प्रसंस्करण वेतन में कार्यान्वित।

प्रणाली को एकीकृत करके अधिकृत बजट योजना के तहत बिल विवरण प्राप्त करने के लिए मानकीकृत प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। सत्यापन के बाद, कोषागार बिलों की प्रक्रिया करते हैं और भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जारी करते हैं।	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा लगभग 8.5 लाख बिल ऑनलाइन जमा किए गए थे।

14. ई-पेंशन https://himkosh.hp.nic.in/treasuryportal

हिमाचल प्रदेश में मासिक आधार पर 1,10,042 पेंशनरों को पेंशन की गणना, संशोधन, प्रसंस्करण और वितरण के लिए 12 जिला कोषागारों में ई-पेंशन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। पेंशन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक शाखाओं/पेंशनरों द्वारा निर्दिष्ट खातों के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन इंटरफेस, पेंशनरों की हेल्पलाइन, पेंशनरों के लिए उनके पेंशन वितरण विवरण देखने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर में सेवानिवृत्ति, परिवार और राजनीतिक पेंशनभोगी शामिल हैं। सॉफ्टवेयर वेब आधारित है और डेटा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र शिमला में केंद्रीय सर्वर पर संग्रहीत है। जीवन प्रमाण एकीकरण भी किया गया है।	कवरेज 100% इस सॉफ्टवेयर द्वारा वर्तमान पेंशनभोगी शक्ति प्रबंधन लगभग 1.34 लाख है। मासिक पेंशन संवितरण लगभग 1200 बैंक शाखाओं के माध्यम से होता है। **पुरस्कार:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण चिह्न पुरस्कार 2006

15. ई-वितरण - ऑनलाइन बजट वितरण प्रणाली

वेब आधारित आवेदन विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को स्वीकृत बजट के वितरण के लिए उनके संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए स्वीकृति पत्र तैयार किए जाते हैं। इसी वितरण के आधार पर कोषागारों से बिलों का भुगतान प्राधिकृत किया जाता है। सॉफ्टवेयर का अन्य अनुप्रयोगों के साथ भी संबंध है।	कवरेज 100% डी.डी.ओ. को ऑनलाइन स्वीकृति पत्र उपलब्ध हैं। eVitran को eBills और iHPOLTIS के साथ एकीकृत किया गया है, जो डी.डी.ओ. को अधिकृत शीर्षों के तहत बिल तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

16. ई-एन.पी.एस. - नई पेंशन योजना

कम्प्यूटरीकृत नई पेंशन योजना सॉफ्टवेयर, नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के योगदान की निगरानी के लिए है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के कुल 72656 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसमें ई-सैलरी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेसिंग भी है। कुल धनराशि (सरकारी योगदान के मिलान सहित) को बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है	कवरेज 100% कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन नई पेंशन योजना का विवरण उपलब्ध है।

और ग्राहकों के विवरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में सूचित किया जाता है।

17. ई-चालान (साइबर ट्रेजरी)

हिमाचल प्रदेश सरकार की एक ऑनलाइन सरकारी रसीद लेखा प्रणाली है। सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने वाले विभाग ई-चालान से जुड़े हुए हैं। कोई नागरिक 24x7 आधार पर नेट बैंकिंग का उपयोग करके सिस्टम पर लॉग इन करके ई-चालान का उपयोग करके सरकारी धन जमा कर सकता है और ट्रेजरी सुविधा काउंटर से ई-चालान बनाने के बाद सीधे बैंक में भी जमा कर सकता है। ई-चालान को एकीकृत किया गया है ऑनलाइन भुगतान के लिए विभागीय आवेदन जैसे वाहन, सारथी, टी.सी.पी. आदि के साथ।

सिस्टम के माध्यम से चालान तेयार किए गए हैं।

18. हिमाचल प्रदेश ए.जी. कार्यालय के लिए सामान्य भविष्य निधि सूचना प्रणाली

हिमाचल प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि सूचना प्रणाली को विशेष रूप से सामान्य भविष्य निधि/पेंशन मुद्दों से संबंधित कर्मचारियों की बातचीत में G2E जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। सामान्य भविष्य निधि विवरण मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

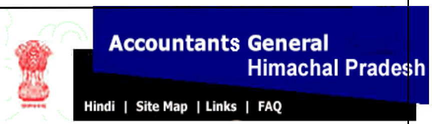

https://aghp.cag.gov.in

19. एसएनए स्पर्श - राष्ट्रीय लेखा प्रणाली

पी एफ एम एस, ई-कुबेर (आर बी आई) और राज्य आई एफ एम आई एस जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी एस एस) के तहत धनराशि के जस्ट-इन-टाइम (जे आई टी) रिलीज को अपनाने के लिए, एनआईसी एचपी राज्य केंद्र ने एसएनए-स्पर्श एप्लिकेशन विकसित किया है, जो निर्बाध निधि प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है और जे आई टी प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत निधि प्रबंधन के लिए इस एप्लीकेशन को राज्य के सभी विभागों में लागू किया गया है।

20. दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली

दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली विकास खंडों के लिए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है, इसके द्वारा खातों के रखरखाव और सभी अनिवार्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत समाधान है। वित्तीय लेनदेन को वाउचर के रूप में दर्ज किया जाता है और पंचायतों के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे विकास कार्यों से जोड़ा जाता है।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के सभी विकास खण्डों में क्रियान्वयन के अधीन है। एक केंद्रीय रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है।

21. रेफनिक (संदर्भ निगरानी प्रणाली)

एक बड़े कार्यालय में फाइलों/पत्रों (विचाराधीन कागजात) की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, अधिकारियों/ आम जनता के लिए इंटरनेट इंटरफेस, विभिन्न अनुभागों में बेहतर निगरानी/कार्यभार के आकलन के लिए स्वत: ईमेल

हिमाचल प्रदेश सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, शिक्षा निदेशालय

22. मुख्य मंत्री रेफनिक

इस सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न संसाधनों जैसे आम जनता, मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों और अन्य बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित स्थानांतरण, विकास, शिकायतों आदि से प्राप्त साधारण पत्र/ फैक्स/ टेलीग्राम/ ई-मेल के रूप में प्राप्त संदर्भों की निगरानी के लिए किया जाता है।

2004 से मुख्यमंत्री कार्यालय में लागू किया गया। वेब-सक्षम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

23. समग्र ई-समाधान - व्यापक लोक शिकायत निवारण प्रणाली

नियम प्रणाली में समस्याओं को हल करने के लिए, शिकायत की निगरानी के लिए एक सामान्य वेब आधारित प्रणाली "समग्र ई-समाधान" विकसित की गई है। वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर नागरिकों द्वारा शिकायतों/मांगों को ऑनलाइन दर्ज करने और बैक-एंड सरकारी कार्यालयों के लिए विकसित कार्य-प्रवाह प्रणाली के माध्यम से उनके निवारण को सक्षम बनाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा चयनित आवेदन की निगरानी करने, चित्रमय रिपोर्ट देखने, आर.पी.जी. विभाग के माध्यम से आवेदन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध और निपटान की गुणवत्ता की निगरानी करने की सुविधाएँ प्रदान करता है ।

https://esamadhan.nic.in
कवरेज: इसे वर्ष 2009 से विभिन्न संगठनों को कवर करते हुए लागू किया गया है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। शिकायतों के निवारण के लिए एकल प्रणाली प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री रेफनिक, जनमंच के साथ एकीकृत किया गया है।

24. वर्क्स प्रबंध सूचना प्रणाली

वर्क्स प्रबंध सूचना प्रणाली में सभी परिचालन स्तरों पर विभाग की कार्य पद्धति शामिल है जैसे अनुभाग, सब-डिवीजन, डिवीजन, सर्कल, जोनल और प्रधान कार्यालय और निम्नलिखित मुख्य कार्य शामिल हैं:
1. वित्त प्रबंधन 2. योजना प्रबंधन 3. ठेकेदार प्रबंधन
4. सामग्री सूची प्रबंधन।
सॉफ्टवेयर के संचालन और पूरी क्षमता का उपयोग करने के प्रयास जारी हैं।

सॉफ्टवेयर जल शक्ति विभाग के 46 मंडलों में लागू किया गया है, पायलट आधार पर ऑनलाइन जल बिल तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रणाली ई-टेंडरिंग के लिए ई-प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर से भी जुड़ी हुई है।

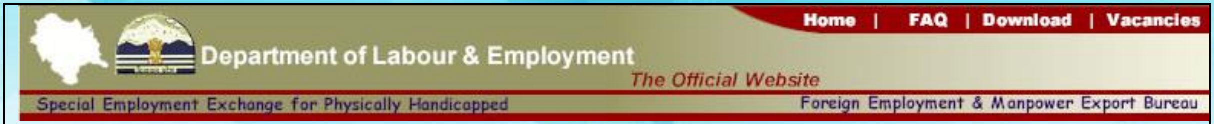

25. रोजगार जॉब पोर्टल https://eemis.hp.nic.in

राज्य और केंद्रीय श्रम और रोजगार विभाग के निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार उम्मीदवार पंजीकरण, रिक्ति बुकिंग, प्रस्तुत करने या प्रायोजित करने, नवीनीकरण, वरिष्ठता और नियमित आवर्तन से शुरू होने वाले राज्य में विभिन्न रोजगार कार्यालयों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए एक कम्प्यूटरीकृत समाधान।

यह वेब सक्षम सॉफ्टवेयर हिमाचल प्रदेश राज्य के लगभग 8 लाख बेरोजगार युवाओं और उद्योग विभाग के साथ पंजीकृत निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए है।

26. कौशल विकास और बेरोजगारी भत्ता प्रबंध सूचना प्रणाली

कौशल विकास और बेरोजगारी भत्ता सॉफ्टवेयर रोजगार कार्यालयों के पंजीकृत उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और लाभार्थियों को भत्ते का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। बेरोजगारी भत्ता भी मासिक आधार पर सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन वितरित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल, 2015 से राज्य के सभी क्षेत्रीय, जिला और उप रोजगार कार्यालयों में लागू किया गया है।

27. OFRIS - ऑनलाइन फैक्टरी पंजीकरण प्रणाली

ऑनलाइन फैक्टरी पंजीकरण प्रणाली एक स्वचालित वेब-आधारित प्रणाली है जो स्वचालित और कार्य-प्रवाह तरीके से भवन निर्माण योजना अनुमोदन और कारखाना पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करती है जिससे पंजीकरण में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलती है। आवेदक को प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चरण की स्थिति के बारे में पता चलता है।

कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों की सं.:
भवन योजना अनुमोदन: 3234
फैक्टरी पंजीकरण: 2991
फैक्टरी नवीनीकरण: 7831
फैक्टरी संशोधन: 1576

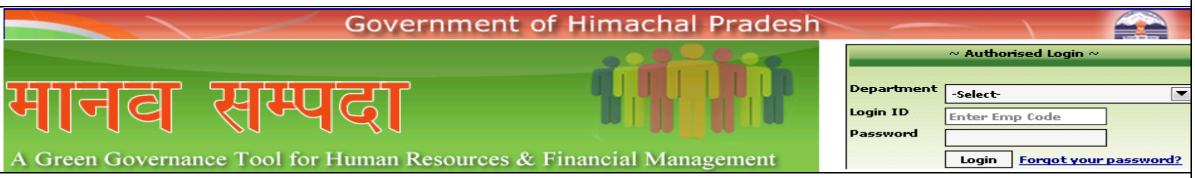

28. मानव संपदा (कार्मिक प्रबंध सूचना प्रणाली)

कार्मिक प्रबंध सूचना प्रणाली (ई-सर्विस बुक) पूर्ण विवरण के साथ कर्मचारी सेवा पुस्तिका की सुविधाजनक और प्रभावी निगरानी के लिए विकसित की गई है। कार्मिक प्रबंध सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए, व्यक्तिगत, पेशेवर, पता, नामांकित व्यक्ति, परिवार, शिक्षा, प्रशिक्षण, अवकाश, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, सेवा इतिहास जैसी जानकारी सभी कर्मचारियों को क्लिक पर उपलब्ध है, जिससे सभी व्यक्तियों को दूरस्थ रूप से अपनी अद्यतन सेवा पुस्तिका देखने में मदद मिलती है।

पुरस्कार: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण 2018 और सी.एस.आई. सस्टेनेन्स अवार्ड 2017, जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2018 - जूरी चॉइस।

राज्य के सभी विभागों/ निगम/ बोर्डों में शत प्रतिशत कार्यान्वित। 2.50 लाख कर्मचारियों को कवर किया गया है।

मोबाइल ऐप्स

सॉफ्टवेयर को 17 राज्यों/ केंद्रीय संगठनों में रेप्लिकट किया गया है, जिसमें 18 लाख से अधिक सेवा पुस्तकें शामिल हैं।

https://ehrms.nic.in

29. हिम अतिथि ऑनलाइन सरकारी अतिथि/विश्राम/सर्किट हाउस बुकिंग

सरकारी अतिथि/विश्राम/सर्किट हाउस/भवन बुकिंग सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन बुकिंग कर्मचारियों और नागरिकों को इस पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन आवास बुक करने में सक्षम बनाती है और पीडब्ल्यूडी, जी ए डी के गेस्ट हाउसों को इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की पेशकश की जा रही है।	https://himatithi.nic.in

30. ई-हिमापूर्ति https://food.hp.nic.in/

वेब सक्षम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से विभाग के कामकाज की प्रभावी निगरानी (विभिन्न कार्यालयों में दर्ज डेटा संकलन द्वारा सभी अनिवार्य रिपोर्ट तैयार करना), नागरिक सेवाएं प्रदान करने और सूचना के अधिकार के सफल कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे 12 जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालयों में लागू किया गया है। सप्लाई चेन और उचित मूल्य की दुकान ऑटोमेशन अब शुरू होगा।	कवरेज: 100% 12 जिलों के सभी 12 जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कार्यालयों में क्रियान्वित किया गया।

31. योजनाएं प्रबंध सूचना प्रणाली

योजनाओं की निगरानी सूचना प्रणाली वित्तीय और भौतिक दोनों मापदंडों का ट्रैक रखते हुए विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए एक पूर्ण समाधान है।	हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर और सिरमौर में लागू किया गया।

32. परीक्षा प्रसंस्करण प्रणाली

विभागीय परीक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण प्रक्रिया को कार्य प्रवाह तरीके से कम्प्यूटरीकृत करने के लिए सामान्यीकृत वेब-सक्षम परीक्षा प्रसंस्करण प्रणाली सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।	एम एस हिपा में कार्यान्वित कियागया। https://himachal.nic.in/hipa पर उपलब्ध है।

33. सड़क परमिट जारी करने की प्रणाली

बंद और प्रतिबंधित सड़कों पर यातायात को विनियमित करने के लिए और नागरिकों को शिमला में विभिन्न सड़कों पर एक सुखद सैर प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अधिनियम के तहत सड़क परमिट जारी करती	हिमाचल प्रदेश सचिवालय और उपायुक्त कार्यालय शिमला में कार्यान्वित।

है। पास/परमिट जारी करने के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित किया गया है।	
34. इनर लाइन परमिट जारी करने की प्रणाली	
सॉफ्टवेयर दूरस्थ जनजातिय जिले किन्नौर से आने वाले आगंतुकों के लिए बेहतर और नियंत्रित तरीके से परमिट जारी करने में प्रशासन की मदद करता है।	किन्नौर जिले में लागू
35. गेटपास जारी करने की प्रणाली	
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आगंतुकों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और विनियमित करने और सुरक्षा को लागू करने के लिए गेट पर फोटो कैप्चरिंग और बार कोड आधारित जांच के साथ सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।	हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लागू किया गया।
36. वेब सक्षम G2C इंटरफेस	
टेलीफ़ोन निर्देशिका, सिविल सूचियें - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय अधिकारी, और हिमाचल प्रदेश सचिवालय पुस्तकालय के लिए वेब आधारित इंटरफ़ेस हैं। यह रिक्तियों, निविदाओं, घोषणाओं, विधान सभा प्रश्न व सूची तथा व्यवसाय कार्यवाही के लिए इंटरफ़ेस भी प्रदान करता है।	https://himachal.nic.in पर उपलब्ध है
37. हाउस अलॉटमेंट प्रबंध सूचना प्रणाली	
सॉफ़्टवेयर को शिमला में अधिकारियों को सरकारी पूल आवास के निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन के लिए विकसित किया गया है। मासिक किराया के साथ सॉफ़्टवेयर के माध्यम से आबंटन की प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। सॉफ़्टवेयर ई-सैलरी से जुड़ा हुआ है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक किराए की मांग उपलब्ध कराई गई है ।	सॉफ़्टवेयर सम्पदा निदेशालय शिमला में कार्यान्वित

38. एकीकृत ऑनलाइन होटल आरक्षण प्रणाली	
iOHRS सॉफ़्टवेयर संभावित मेहमानों/ पर्यटकों/ आगंतुकों या आम जनता के लिए आवास की ऑनलाइन उपलब्धता स्थिति और किसी भी समूह/ होटलों की श्रृंखला की तत्काल ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। आवास का ऑनलाइन आरक्षण और होटलों में पहले से किए गए आरक्षण को रद्द करना, मेहमानों द्वारा स्वयं या अधिकृत कार्यालयों/ एजेंटों के माध्यम से तत्काल किया जा सकता है। सॉफ़्टवेयर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन चैनल मैनेजर एक्सिस-रूम, मोबाइल-ऐप, ईमेल और एस.एम.एस. गेटवे के साथ एकीकृत है। एक्सिस-रूम चैनल मैनेजर के साथ एकीकरण से समूह/ होटलों की श्रृंखला के सभी होटलों की उपस्थिति को	सॉफ़्टवेयर को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में अक्टूबर 2001 से लागू किया गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक बुकिंग की गई है। परियोजना को वर्ष 2015 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण चिह्न

बिभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर अपने होटलों की पूरी सूची बनाकर सभी लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स पर सक्षम बनाता है।	पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

39. चुनाव सपोर्ट

सॉफ्टवेयर को मतदान दलों के यादृच्छिकीकरण, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करने, चुनाव परिणामों के संकलन, भारत चुनाव आयोग वेब सर्वर और दूरदर्शन को डेटा ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। मोबाइल आधारित मतदान रुझान सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। भारत चुनाव आयोग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपायुक्तों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई। लोकसभा 2014 के चुनावों में डी.आई.एस.ई. सॉफ्टवेयर समर्थन प्रदान किया जा रहा है।	वर्ष 2007 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सभी 12 जिलों को सहायता प्रदान की जा रही है।

40. पी.आर.आई./ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव - मतदाता सूची तैयार करना

सॉफ्टवेयर पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए मौजूदा भारत चुनाव आयोग रोल से मतदाता सूची बनाने के लिए है, डेटा प्रविष्टि कार्य को कम करता है। राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण सहित पंचायती राज संस्थान प्रतिनिधियों को कवर करने के लिए सॉफ्टवेयर का विस्तार किया गया है। 2010 से इस एप्लिकेशन का उपयोग करके मतदाता सूची तैयार की जा रही है और सभी वार्षिक संशोधन मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। हाल ही में हुए चुनावों में 2015 के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया है। अब तक मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर बनाई गई मतदाता सूची का उपयोग करके 2 आम चुनाव आयोजित किए गए हैं। अब चुनाव प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस विकसित किया जा रहा है। अब ई.वी.एम. प्रबंधन और मतदान दिवस की प्रक्रियाएं भी स्वचालित हो गई हैं, और 2022-23 के चुनावों में सॉफ्टवेर का उपयोग किया गया है।

41. उर्जा - विद्युत परियोजना निगरानी प्रणाली

स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई.पी.पी.) के माध्यम से बिजली के विकास और उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न बिजली परियोजनाओं पर गहन निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश उत्पादकों ने इन परियोजनाओं को विकसित नहीं किया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए, निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी बिजली परियोजनाओं की कड़ी निगरानी के लिए सूचना प्रणाली विकसित की गई है। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि भुगतान और उपयोग की निगरानी की जा रही है।	सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन के अधीन है और निगरानी उद्देश्यों के लिए परियोजनाओं की स्थिति दर्ज करने के लिए परियोजना विकासकर्ताओं और उत्पादकों को यूजर आई.डी. दी गई है।

42. रोहतांग पास परमिट जारी करने की प्रणाली	https://hpkullu.nic.in
इस एप्लिकेशन का उपयोग आम नागरिकों के साथ-साथ जिला कुल्लू के अधिकारियों द्वारा रोहतांग दर्रे पर जाने वाले वाहनों के लिए परमिट बनाने के लिए किया जाता है। इस एप्लिकेशन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है, जहां परिभाषित कोटा के अनुसार वाहनों को प्रतिदिन अनुमति दी जाती है।	यह परियोजना सितंबर, 2015 को लागू की गई थी। अब तक लगभग 9,94,180 परमिट सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए हैं और रोहतांग दर्रे पर जाने के लिए परमिट जारी करने में लगभग रु.41.62 करोड़ कर एकत्र किये गए हैं।

43 विशेष सड़क कर प्रणाली	
विशेष सड़क कर एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जिसका उपयोग परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधिकारियों द्वारा स्टेज ढुलाई, वाहन के टाइम टेबल और रूट परमिट जारी करने के लिए किया जाता है। एप्लिकेशन बसों में बैठने की क्षमता, दूरी और सड़कों की श्रेणी जैसे रोड परमिट मापदंडों के आधार पर मासिक प्रीपेड विशेष रोड टैक्स की गणना स्वत: करता है।	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 2013 से कर के रूप में रु.92.67 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

44. स्वयंसिद्धम शिक्षा पोर्टल	https://rmsahimachal.nic.in
पोर्टल को गुणवत्तापूर्ण सामग्री के लिए ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करके सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में शिक्षकों और छात्रों की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का नवीनतम शिक्षण सहायक ऑनलाइन प्रशिक्षण संभव है।	ऑनलाइन किताबें, बहुविकल्पीय प्रश्न-उत्तर, परीक्षण, पिछले बोर्ड परीक्षा के पेपर, पाठ योजना, संकेतक, छात्रों के प्रश्न, सर्वोत्तम उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं।

45. ई-स्टॉक प्रबंधन प्रणाली

उपभोज्य और गैर-उपभोज्य स्टॉक वस्तुओं की खरीद, सूची नियंत्रण और रखरखाव गतिविधियों को संभालने के लिए वेब सक्षम समाधान। उपभोज्य वस्तुओं की खरीद और जारी करने के लिए मापांक लागू किया गया है। गैर-उपभोग्य सामग्रियों और हार्डवेयर के रखरखाव के लिए मापांक विकसित किए जा रहे हैं।	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश में सॉफ्टवेयर का परीक्षण चल रहा है।

46. राज्य टेलीफोन निर्देशिका सेवा

https://himachalservices.nic.in/hpcivil/Home?TabId=2

हिमाचल प्रदेश राज्य टेलीफोन निर्देशिका सेवा: उपयोगकर्ता विभागों/ जिलों के टेलीफोन नंबरों को अपडेट/ जोड़ सकते हैं। उपयोगकर्ता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन राज्य टेलीफोन निर्देशिका सेवा का उपयोग करके विभागों/ जिलों के टेलीफोन नंबर, अधिकारियों के नाम खोज सकते हैं। ईमेल, टेलीफोन नंबर, पी.डी.एफ. फोन निर्देशिका के लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं।	लगभग 8000 सरकारी अधिकारियों का डेटा खोज योग्य प्रारूप में और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से एंड्रॉयड, विंडोज़ और एप्प्ल प्लेटफार्मों पर मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।

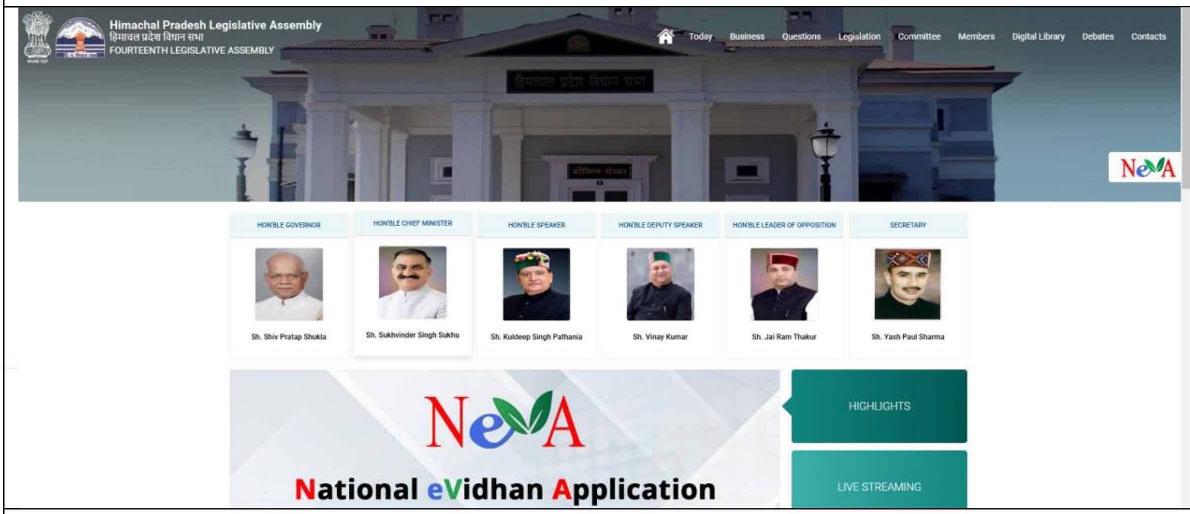

47. ई-विधान/ NeVA परियोजना

https://hpvs.neva.gov.in/
https://cmshpvs.neva.gov.in/

NeVA (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन) एक कागज रहित समाधान है, जिसे शुरू में एचपी विधानसभा में ई-विधान के रूप में विकसित और कार्यान्वित किया गया था, जहां घर के सभी कामकाज इस एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, जिसमें प्रशासनिक सचिवों के लिए सवालों, समितियों आदि को ऑनलाइन मोड में जवाब देने के लिए इंटरफेस भी शामिल है। केवल।	हिमाचल प्रदेश विधानसभा एप्लिकेशन और वेबसाइट दोनों को राष्ट्रीय मानक और **GIGW** अनुरूप **NeVA** प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

48. मध्याह्न भोजन स्वचालित रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (लघु संदेश सेवा आधारित)

नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने और साथ ही साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तन हुए हैं और अब इसे "स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम" के रूप में जाना जाता है। लगभग 11 लाख स्कूलों में 10 करोड़ से अधिक पात्र स्कूली बच्चे इस योजना से लाभान्वित होते हैं। विभिन्न राज्यों के स्कूलों में नामांकन और भोजन परोसने के प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्याह्न भोजन स्वचालित रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर को एक उत्पाद के रूप में विकसित किया गया है ताकि कोई भी राज्य शिक्षा विभाग इसका उपयोग कर सके। एकत्र किए गए डेटा को दैनिक आधार पर राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर https://mdmhp.nic.in पर उपलब्ध है और देश के **5** लाख से अधिक स्कूलों को कवर करते हुए **17** राज्यों में लागू किया गया है।

49. मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए हिम प्रगति सॉफ्टवेयर https://himpragati.nic.in

मुख्यमंत्री कार्यालय विभिन्न योजनाओं, औद्योगिक निवेश, रोजगार लक्ष्यों, राज्य में लागू की जा रही बड़ी परियोजनाओं, बजट आश्वासनों, घोषणाओं आदि की प्रगति की निगरानी कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र ने इन परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें हितधारक विभागों और औद्योगिक उद्यमियों द्वारा निर्देश जारी करने की विशेषता और प्रत्यक्ष डेटा प्रविष्टि करने की सुविधाएं हैं। निम्नलिखित को शामिल करके मल्टीपल पैरामीटर मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस जोड़े गए हैं:

- बजट आश्वासन
- हिम विकास समीक्षा के तहत विभागीय मानदंड
- रोजगार सृजन लक्ष्य
- निवेश लक्ष्य
- प्रमुख परियोजनाएं, उनके निष्पादन की स्थिति, मुद्दे और चिंता का समाधान
- निवेश लक्ष्य और समझौता ज्ञापन
- विभिन्न अन्य योजनाएं
- मुख्यमंत्री घोषणाएँ
- राइजिंग हिमाचल बैनर के तहत निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- विकास संकेतक-हिम विकास समीक्षा

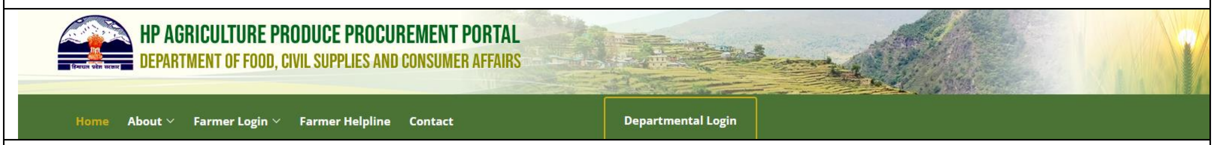

50. हिमाचल प्रदेश कृषि उपज खरीद पोर्टल https://hpappp.nic.in

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज खरीद पोर्टल, हिमाचल प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाता है। यह प्रणाली कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण और उनके बैंक खातों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। यह राज्य के भूमि अभिलेख प्रणाली के साथ एकीकृत है।

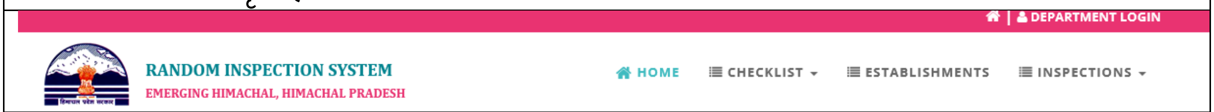

51. सामान्य निरीक्षण प्रणाली https://cis.hp.nic.in

हिमाचल सरकार ने निरीक्षण पर स्पष्टता सुनिश्चित करने, निरीक्षण की आवृत्ति, और दोहराव को कम करने के उद्देश्य से निरीक्षण प्रणाली में सुधार के लिए "व्यापार करने में आसानी" के हिस्से के रूप में "केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली" का गठन किया है। इस सॉफ़्टवेयर सक्षम निरीक्षण प्रणाली का उद्देश्य व्यावसायिक नियमों को सरल बनाने और निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और जोखिम आधारित मूल्यांकन के आधार पर उद्योग विभाग (बॉयलर), श्रम विभाग और हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समकालिक करना सुनिश्चित करना है।

52. बड़े बांध सुरक्षा विश्लेषण प्रबंध सूचना प्रणाली https://hpsdma.nic.in/dams

यह सॉफ्टवेयर, हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा निदेशालय के तहत 23 बड़े बांध स्थलों की निगरानी को दैनिक मापदंडों में तीन बार सुबह 9:00 बजे, दोपहर 2:00 बजे और शाम 7:00 बजे दर्ज करने में सक्षम बनाता है। सुरक्षा संबंधी मापदंडों को भी समय-समय पर ऑनलाइन तरीके से लिया जाता है। उच्च अधिकारी इन मापदंडों में किसी भी तरह की असमानता होने की स्थिति में समय पर कार्रवाई करने के लिए डेटा एनालिटिक्स की मदद से इन मापदंडों की निगरानी कर सकते हैं, ताकि आपदाओं से बचा जा सके।

https://hpsdma.nic.in/dams

53. एच पी राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एमआईएस https://hpsdmaplan.nic.in/sdmf

एस डी एम एफ (राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) एम आई एस राज्य सरकार द्वारा एस डी एम ए के माध्यम से धन के ऑनलाइन संवितरण के लिए एक पहल है। यह एक एकल साइन-ऑन, भूमिका-आधारित एप्लिकेशन है जो सभी हितधारकों जैसे विभागों/निष्पादन एजेंसियों, डी डी एम ए, एस डी एम ए, परियोजना और तकनीकी मूल्यांकन समितियों (**PAC** और **TAC**), राज्य कार्यकारी समिति (**SEC**) और तकनीकी सलाहकारों को प्रस्तुत करने के लिए कवर करता है। प्रस्ताव, मूल्यांकन, अनुमोदन, धन का संवितरण और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी। एप्लिकेशन को राज्य में लागू कर दिया गया है और सभी हितधारकों ने एप्लिकेशन को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है।

संस्थान नवाचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, अध्ययन और शिक्षण उद्देश्य के लिए इस एप्लिकेशन के माध्यम से एसडीएमए के साथ ऑनलाइन साझेदारी भी कर सकते हैं।

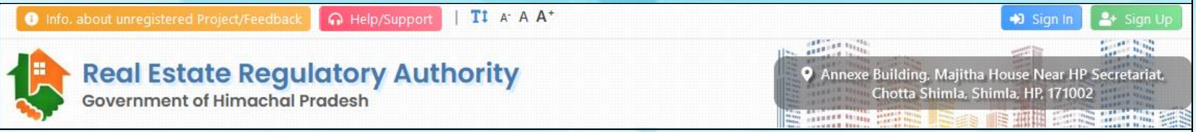

54. हि.प्र. रेरा प्रबंधन सूचना प्रणाली https://hprera.nic.in

हिमाचल प्रदेश - रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण प्रबंधन सूचना प्रणाली अपनी तरह का अनूठा सॉफ्टवेयर है जो देश के दूरस्थ भाग से भी प्रमोटरों, एजेंटों, घर खरीदारों और नागरिकों के उपयोग में आसानी और सरलता प्रदान करता है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना, रियल एस्टेट परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी करना और रियल एस्टेट खरीदारों में विश्वास पैदा करना है। इसमें शिकायत समाधान, ऑनलाइन भुगतान और विवादों के समाधान के लिए इंटरफेस है।
एप्लिकेशन को NGC 1.0 (नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

55. एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के चालान https://bannedsup.hp.nic.in/

प्रतिबंधित एकल उपयोग पॉलिथीन (एस यू पी) चालान सॉफ्टवेयर, हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्राधिकरणों को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मोबाइल ऐप का उपयोग करके प्रतिबंधित एकल उपयोग पॉलिथीन वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों या संस्थानों का चालान करने में सक्षम बनाना है। यह वेब एप्लिकेशन उच्च अधिकारियों (जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और नोडल विभाग) को विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई चालान संबंधी गतिविधियों की निगरानी करने में सहायता करता है। चालान किया गया व्यक्ति या संस्थान क्यूआर कोड या भुगतान गेटवे का उपयोग करके ऑनलाइन जुर्माना/चालान राशि का भुगतान कर सकता है। यह सुविधा मोबाइल ऐप और वेब एप्लिकेशन दोनों पर उपलब्ध है।

6.0 राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्टवेयर परियोजनाएं

(विकास/ कार्यान्वयन/ सहायता/ परामर्श पहलू)

1. परियोजना का नाम : प्रगति

प्रगति (सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन) एक बहुउद्देश्यीय और मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है। प्रगति एक अनूठा एकीकृत और परस्पर प्रभाव डालना वाला प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को दूर करना और साथ ही साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। बैठक की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश ने प्रगति के सभी सत्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

2. परियोजना का नाम: ई-समीक्षा

ई-समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय, ऑनलाइन प्रणाली है। प्रत्येक निर्णय के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई को संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ एजेंसी द्वारा स्थिति में परिवर्तन होने पर या कम से कम हर महीने अद्यतन किया जाता है।	ई-समीक्षा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और अनुवर्ती कार्रवाई नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाती है। उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान की गई।

3. परियोजना का नाम: AEBAS

AEBAS (आधार सक्षम बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली) आधार प्रमाणीकरण पर आधारित बायो-मेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। यह वास्तविक समय की निगरानी के साथ क्लाउड आधारित समाधान है। यह मल्टीप्लेटफॉर्म और फॉर्म फैक्टर पर काम करता है।	हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए परियोजना लागू की गई है। 96 केंद्र सरकार और 20 राज्य सरकार के विभागों में सॉफ्टवेयर लागू किया है। पोर्टल पर 63,636 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं।

4. परियोजना का नाम: जीवन प्रमाण

जीवन प्रमाण पेंशनरों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संस्था के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।	केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के बायोमैट्रिक आधारित जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया

	गया है। राज्य में 48000 से अधिक पेंशनभोगियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है।
5. परियोजना का नाम: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0	
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वन-स्टॉप समाधान है जिसके माध्यम से छात्र आवेदन, आवेदन प्राप्ति, प्रसंस्करण, मंजूरी और छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति के वितरण से शुरू होने वाली विभिन्न सेवाओं को सक्षम किया जाता है। इस पहल से, छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे बिना किसी लीक के सीधे लाभार्थियों के खातों में धनराशि स्थानांतरित की जा सकेगी।	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वर्तमान में पोर्टल पर कुछ योजनाएँ सक्रिय हैं और पोर्टल का उपयोग करके इन योजनाओं के लिए अनुरोध और प्रसंस्करण किया जाता है।
6. परियोजना का नाम: ई-बालनिदान	
ई-बालनिदान सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के लिए एक वेब सक्षम शिकायत प्रबंधन प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। इस वेब अनुप्रयोग का मूल उद्देश्य बाल अधिकारों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करना है और आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसी शिकायतों को पूरे देश में संबंधित इकाई/कार्यालय/विभाग को अग्रेषित करके ऑनलाइन ट्रैक करना है। आवेदन https://ebaalnidan.nic.in पर ऑनलाइन किये जा सकते हैं, और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट से भी उपलब्ध है।	राष्ट्रीय आयोग में लागू किया गया।
7. परियोजना का नाम: ई-प्रोक्योरमेंट - ऑनलाइन टेंडरिंग	
ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के लिए एक भुगतान परियोजना के रूप में शुरू की गई है और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र सेवा इनकारपोरेटेड के माध्यम से कार्यान्वयन के अधीन है। परियोजना में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, जनशक्ति, प्रशिक्षण घटक शामिल हैं और राज्य सरकार के 38 विभागों में सभी निविदाओं को शामिल किया जाएगा। विभाग द्वारा निर्धारित सीमा मूल्य के आधार पर 16,750+ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 29,928 से अधिक निविदाएं प्रकाशित की गई हैं।	38 विभागों/संगठनों में कार्यान्वित ।
8. परियोजना का नाम: ईग्रंथालय - लाइब्रेरी स्वचालन सॉफ्टवेयर	
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित मानक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर सूचना प्रसार के लिए वेब-इंटरफेस के साथ देश के सभी पुस्तकालयों में कार्यान्वयन के लिए बनाया गया है।	हि.प्र. सचिवालय, हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान, हि.प्र. विधानसभा, विज्ञान और

	प्रौद्योगिकी विभाग के पुस्तकालयों में कार्यान्वित।
9. परियोजना का नाम: ई-जागृति - उपभोक्ता आयोगों का कम्प्यूटरीकरण	
उपभोक्ता आयोगों का कम्प्यूटरीकरण राज्य में आयोगों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है। https://confonet.nic.in वेबसाइट पर वाद सूची और निर्णय प्रतियों के लिए नागरिक इंटरफेस उपलब्ध हैं।	कवरेज: 100% राष्ट्रीय परियोजना के तहत राज्य और 4 जिलों शिमला, धर्मशाला, मंडी और ऊना में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण किया गया है।
10. परियोजना का नाम: भारत का राष्ट्रीय पोर्टल	
भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सूचना और सेवाओं के लिए एकल विंडो अभिगम को सक्षम करने के लिए, हिमाचल प्रदेश द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित बहुत सारी सामग्री का योगदान दिया गया है। राष्ट्रीय पोर्टल के राज्य समन्वयक को इस योगदान हेतु वेब-रत्न स्वर्ण आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है।	हिमाचल प्रदेश द्वारा देश भर में दूसरे स्थान पर उच्चतम सामग्री का योगदान किया गया और अधिकांश सेवाओं/ फॉर्मो/ योजनाओं/ अधिनियमों/ नियमों के लिए व्यवस्थित तरीके से योगदान दिया।
11. परियोजना का नाम: AGMARKNET - कृषि विपणन सूचना प्रणाली नेटवर्क	
निकनेट आधारित कृषि विपणन सूचना प्रणाली नेटवर्क (AGMARKNET) बाजार मूल्यों पर प्रभावी सूचना विनिमय के लिए देश भर में स्थित सभी महत्वपूर्ण कृषि उपज बाजार समितियों, राज्य कृषि विपणन बोर्डों/ निदेशालयों और ओ.एम.आई. क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ने के लिए है।	कवरेज: 41 बाजार (हिमाचल प्रदेश में शामिल बड़े/छोटे) 100% कवरेज। पोर्टल पर ऑनलाइन दरें, मार्केट प्रोफाइल भी उपलब्ध है।
12. परियोजना का नाम: MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)	
सॉफ्टवेयर को परियोजना की प्रगति की निगरानी करने और सीधे पंचायतों से लाभार्थियों के विवरण प्राप्त करने और पारदर्शिता के लिए इंटरनेट पर डेटा पोर्ट करने के लिए लागू किया गया। सभी फंड इलेक्ट्रॉनिक कोष प्रबंधन प्रणाली के जरिए ट्रांसफर होते हैं। http://nrega.nic.in	कवरेज: राज्य में 100% हिमाचल प्रदेश के लिए सक्रिय श्रमिकों के लिए आधार सीडिंग 85% है।
13. परियोजना का नाम: एन.ई.जी.पी. - कृषि	
एन.ई.जी.पी. - कृषि मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी और सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। ऐसे सभी एप्लिकेशन, जो पहले से ही भारत सरकार/ राज्य स्तर पर विकसित किए गए हैं, को एन.ई.जी.पी.-	कार्य प्रगति पर है, कार्यान्वयन चल रहा है।

ए के तहत परिकल्पित केंद्रीय कृषि पोर्टल (सी.ए.पी.) और राज्य कृषि पोर्टल (एस.ए.पी.) के साथ एकीकृत किया जाएगा।	
14. परियोजना का नाम: ई-पी.आर.आई. सुइट	
पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के अधिकारिता, सक्षमता और उत्तरदायित्व के उद्देश्यों के साथ, और सेवाओं के कुशल वितरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर ई.पी.आर.आई. आवेदन राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र मुख्यालय द्वारा विकसित किया गया है।	सभी हितधारकों के साथ साथ ही भारत सरकार सूचीबद्ध एजेंसियाँ के विकास के लिए सॉफ्टवेयर समाधान कार्य प्रगति पर है ।
15. परियोजना का नाम: एन.जी.डी.आर.एस. (राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली)	
कुमारसेन और सुन्नी तहसीलों में फरवरी 2019 में पायलट योजना के साथ राज्य के सभी स्व-नियामक संगठन में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र पुणे टीम की मदद से राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली सॉफ्टवेयर को अनुकूलित किया जा रहा है।	यह एप्लिकेशन राज्य के सभी व्यवहार्य एसआरओ (उप-पंजीयक कार्यालयों) में लागू किया गया है। भूमि रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए 'माई डीड' पायलट परियोजना शुरू की गई है।
16. परियोजना का नाम: HIMXLN - विस्तारित लाइसेंसिंग नोड	
सॉफ्टवेयर हितधारकों को दवा निर्माण और वितरण लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी को सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन के अधीन है और दवा निर्माताओं को दवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाता है। यह एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जिसका उपयोग दवा निर्माता अपने कार्यालय/ घर से राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालयों के साथ बातचीत के लिए करते हैं।	कार्यान्वित।
17. परियोजना का नाम: ई-जेल सॉफ्टवेयर	
ई-जेल सॉफ्टवेयर को राज्य की सभी जेलों में लागू किया गया है और यह कैदी विवरण, प्रवेश/निकास, फोटो, प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस विवरण आदि को कैप्चर करता है। रिश्तेदारों और जांच अधिकारी के साथ कैदी वी.सी. देश में पहली बार है और इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल एक ऑनलाइन वेब-इंटरफ़ेस के माध्यम से किया जा रहा है। । जेलवार्ता ने मंथन पुरस्कार 2014 जीता है।	राज्य के सभी 20 जेलों में लागू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जेल वार्ता परिजन व जांच अधिकारी के साथ नियमित रूप से की जा रही है।
18. परियोजना का नाम: आई.वी.एफ.आर.टी. (आप्रवासन, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग)	

आप्रवासन, वीजा और विदेशियों के पंजीकरण और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग भारत के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले विदेशियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। जिलों में पुलिस अधीक्षक को विदेशी पंजीकरण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और आप्रवासन, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग के तीन मॉड्यूल हैं, अर्थात् सी-एफ.आर.ओ., सी-फॉर्म और एस-फॉर्म। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसके कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है।	सभी जिलों में कार्यान्वित किया गया।
19. परियोजना का नाम: ई-अस्पताल और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली	
ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओ.आर.एस.) आधार आधारित ऑनलाइन पंजीकरण और नियुक्ति प्रणाली के लिए देश भर के विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने के लिए एक ढांचा है, जहां अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से काउंटर आधारित ओ.पी.डी. पंजीकरण और नियुक्ति प्रणाली को डिजिटल किया गया है। यदि रोगी का मोबाइल नंबर यू.आई.डी.ए.आई. के साथ पंजीकृत है, तो पोर्टल विभिन्न अस्पतालों के विभिन्न विभागों के साथ आधार संख्या के अपने ग्राहक डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानने का उपयोग करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा प्रदान करता है।	ई-हॉस्पिटल और ओआरएस प्रणाली को मेडिकल कॉलेज मंडी, सिविल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और क्षेत्रीय अस्पतालों में लागू किया जा रहा है। नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली को अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
20. परियोजना का नाम: स्पैरो – ए.पी.ए.आर./ए.सी.आर. की ऑनलाइन फाइलिंग	
स्पैरो परियोजना भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक संपत्ति रिपोर्ट का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। अधिकारी अपनी संपत्ति का रिटर्न ऑनलाइन भी भेज सकते हैं।	सॉफ्टवेयर हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
21. परियोजना का नाम: पी.एम. किसान	
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सॉफ्टवेयर छोटे और जरूरतमंद किसानों को तिमाही आधार पर वित्तीय मदद वितरण को सक्षम बनाता है और इसे राज्य में जनवरी 2019 में लागू किया गया है। वर्तमान में, इन लाभार्थियों को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशिष्ट किसान पहचान दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।	सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, हर तिमाही में 8.8 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। लगभग 10% लाभार्थियों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
22. परियोजना का नाम: सर्विस प्लस फ्रेमवर्क	

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र के सर्विस प्लस ढांचे का उपयोग अलग-अलग होस्टिंग प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी या एप्लिकेशन के सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को त्वरित रूप से विकसित और तैनात करने के लिए किया जा सकता है। यह बहुत ही कम समय में मानक सेवा परिनियोजन को सक्षम बनाता है। इसका उपयोग हिमाचल प्रदेश के जिलों में कोविड-19 महामारी के दौरान ई-पास बनाने, संपर्क का पता लगाने और कोविड-19 संदिग्धों की निगरानी के लिए किया गया है।	जिला कांगड़ा और अन्य जिलों में ई-पास जारी करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान इस ढांचे का उपयोग किया गया है। इस पहल की काफी सराहना हो रही है।
23. परियोजना का नाम: दर्पण मुख्यमंत्री डैशबोर्ड	
मुख्यमंत्री और डी.एम. डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से डेटा को कैप्चर करता है और विश्लेषण के लिए सी.एम./डी.एम. डैशबोर्ड पर कई तरीकों से प्रदर्शित करता है।	सॉफ्टवेयर मुख्यमंत्री कार्यालय और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सिरमौर जिलों में लागू किया गया है।
24. परियोजना का नाम: एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आई.सी.जे.एस.)	
राज्य में न्यायालयों, पुलिस, अभियोजन, कारागार और फोरेंसिक विभागों को ऑनलाइन मोड में एकीकृत करके इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है। पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके लिए प्रशिक्षण, डेमो का आयोजन किया जा रहा है।	ई-फोरेंसिक, ई-जेल सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जबकि ई-अभियोजन कार्यान्वयन के अधीन है और अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर एकीकरण प्रस्तावित है।
25. परियोजना का नाम: S3WaaS - एक सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट	
S3WaaS एक सेवा के रूप में एक सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट है जो एन आई सी के राष्ट्रीय क्लाउड पर होस्ट की गई एक वेबसाइट बनाने और तैनात करने वाला उत्पाद है। यह GIGW अनुरूप टेम्पलेट्स का उपयोग करके सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है जो अत्यधिक अनुकूलन योग्य हैं और स्केलेबल सॉफ़्टवेयर परिभाषित बुनियादी ढांचे पर निर्बाध रूप से तैनात किए जा सकते हैं।	हिमाचल प्रदेश की सभी जिला वेबसाइटों को S3WaaS प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सभी जिला वेबसाइटों को S3WaaS प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करने वाला पहला राज्य था। एन आई सी हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र की द्विभाषी वेबसाइट भी S3WaaS प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गई है।

7.0 राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख परियोजनाएं
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित

1. परियोजना का नाम: Covid19cc.nic.in पोर्टल और RT-PCR मोबाइल ऐप	
सॉफ्टवेयर पूरे देश में आर.टी.-पी.सी.आर. और रैपिड एंटी बॉडी मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं के उपयोगकर्ताओं की सत्यापन सूची (white listing) के लिए विकसित और कार्यान्वित किया गया है। देश के 31 राज्यों में 10 हजार से ज्यादा वेब यूजर्स और 2 लाख मोबाइल ऐप यूजर्स, 8000+ लैब्स के जरिए से कोविड-19 आर.टी.-पी.सी.आर. टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आर.टी.-पी.सी.आर. मोबाइल एप्प नमूना संग्राहकों द्वारा उपयोग के लिए विकसित किया गया है ताकि एकत्र किए जा रहे प्रत्येक आर.टी.-पी.सी.आर. नमूने की सूचना का प्रबंधन वे आसानी से कर सकें।	सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक चल रहा है, 31 दिसंबर 2021 तक 32 करोड़ नमूने एकत्र किए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की आवश्यकताओं के अनुसार 14 एस.आर.एफ. संशोधन किये हैं।
2. परियोजना का नाम: ऑक्सीकेयर प्रबंध सूचना प्रणाली और ऑक्सीकेयर मोबाइल ऐप	
भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए OCMIS - ऑक्सीकेयर प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ 'ऑक्सीकेयर' मोबाइल एप्प, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के लिए विकसित की गई है। सॉफ्टवेयर को तेजी से विकसित किया गया है और जून 2021 में लॉन्च किया गया है, कार्यान्वयन के दौरान इसमें सुधार और संशोधन किए जा रहे हैं क्योंकि पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा इस उपकरणों की प्राप्ति, प्रेषण और अंतिम प्राप्ति और व्यवस्थित तरीके से कामकाज की निगरानी के लिए निहितार्थ है।	जून-जुलाई 2021 में भारत के सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया और अन्य स्वास्थ्य उपकरणों को शामिल करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं।
3. परियोजना का नाम: मिशन भर्ती	
केंद्र सरकार के विभागों में राष्ट्रीय स्तर पर रिक्तियों को भरने की निगरानी के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर प्रत्येक रिक्ति को एक परियोजना के रूप में लेता है जिसे परिभाषित लक्ष्यों के अनुसार ट्रैक किया जा सकता है।	सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसके डैशबोर्ड को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वास्तविक कंप्यूटरिकृत प्रणाली के डैशबोर्ड में अपनाया गया है।
4. परियोजना का नाम: नोटीफीकेशन एक सेवा के रूप में	

नोटीफीकेशन एक सेवा के रूप में किसी भी परियोजना में लघु संदेश सेवा की लागत में कटौती करने के लिए एक सामान्यीकृत समाधान है जहां उपयोगकर्ता ईमेल और/या मोबाइल नंबर को कुछ लाभ प्रदान करने या कुछ सरकारी/ अन्य लेनदेन, ई-फाइल, ईमेल इत्यादि के उपार्जन के लिए कैप्चर किया जाता है। उपयोगकर्ता को मोबाइल ऐप का उपयोग करना है और फिर चयनित सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के लिए मोबाइल/डेस्कटॉप पर सूचनाओं का विकल्प चुनना है। डेस्कटॉप पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ता को मोबाइल एप्लिकेशन में एक लिंक पर क्लिक करना है।	सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और हिमाचल सरकार के अनुप्रयोगों पर परीक्षण किया गया है जो कार्यान्वयन के लिए लंबित है।
5. परियोजना का नाम: सरकारी इंट्रानेट पोर्टल	
ईमेल, ई-फाइल्स, कैलेंडर, मीटिंग्स, कार्यों, लक्ष्यों और अन्य विभागीय योजना गतिविधियों के लिए एक खाते के माध्यम से सभी सरकारी इंटरैक्शन/बातचीत के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करना।	कार्य प्रगति पर है।
6. परियोजना का नाम: शिकायत अपीलीय समिति ई-पोर्टल	
शिकायत अपीलीय समिति (जी.ए.सी.) का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2022 के नियम 3ए(3) के अनुसार शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए पीड़ित डिजिटल नागरिक को विकल्प प्रदान करना है। पोर्टल नागरिकों को मध्यस्थ निर्णयों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। उनकी शिकायतें और जी.ए.सी. द्वारा संसाधित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है ।	जी ए सी सचिवालय की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित आधार पर नई सुविधाओं का विकास और कार्यान्वयन किया जा रहा है।

संदर्भ के लिए क्रम 3-6 के स्क्रीन शॉट नीचे दिए गए हैं:

मिशन भर्ती (4)

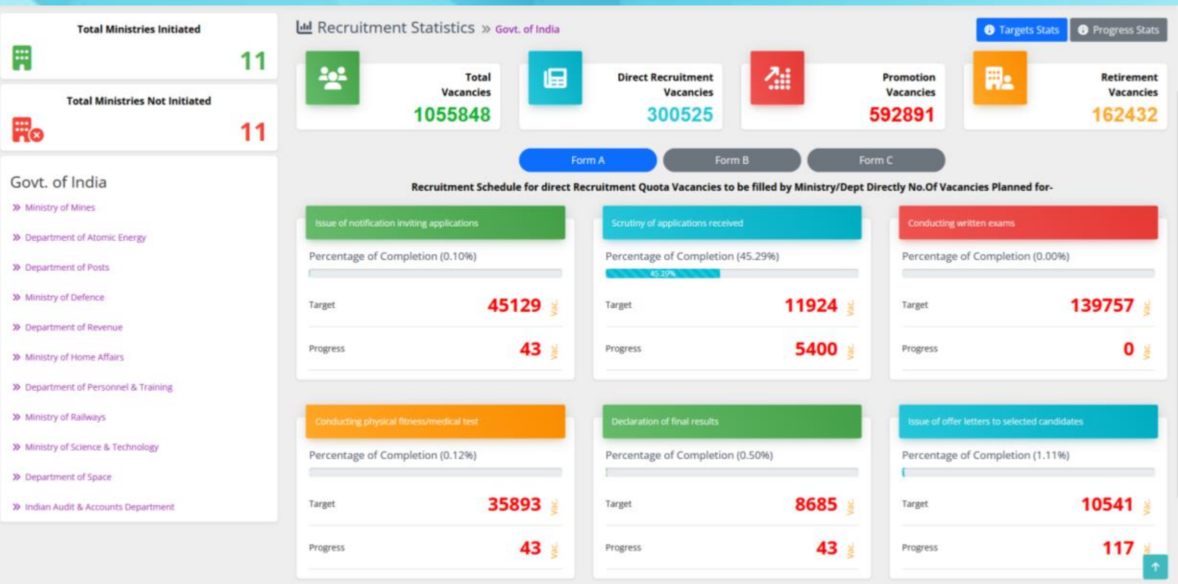

नोटीफीकेशन एक सेवा के रूप में (5)

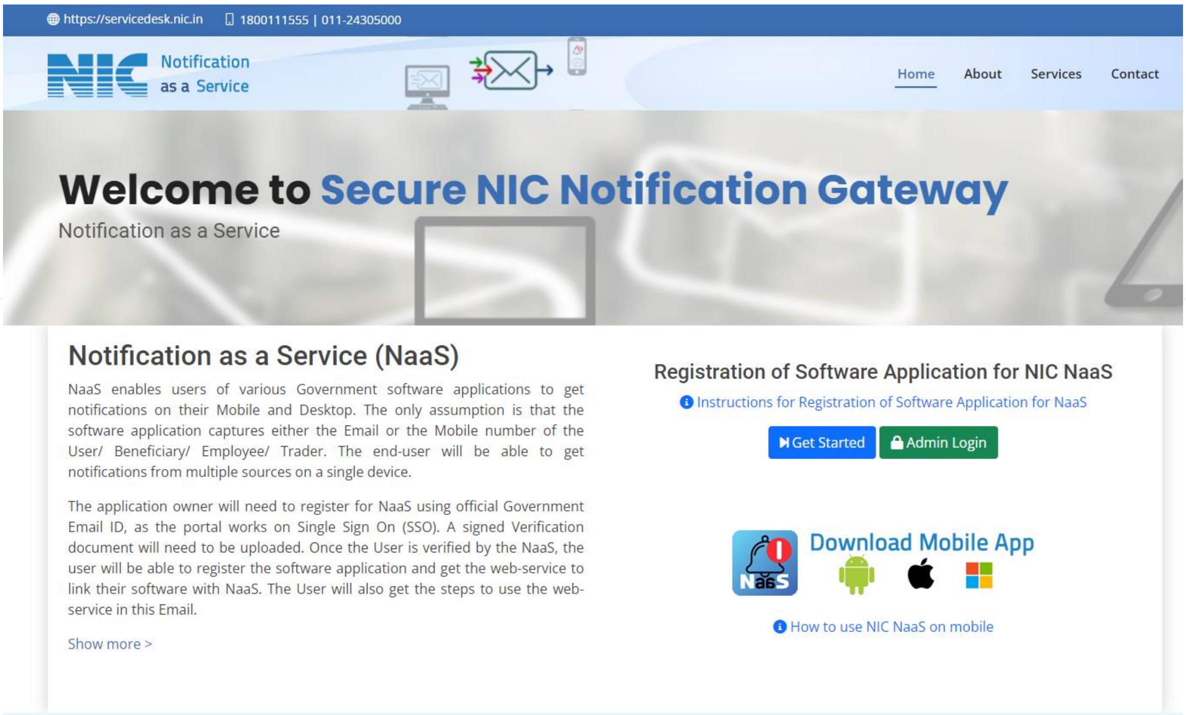

सुरक्षित सरकारी इंट्रानेट पोर्टल (6)

जी.ए.सी. ई-पोर्टल (7)
(शिकायत अपीलीय समिति)

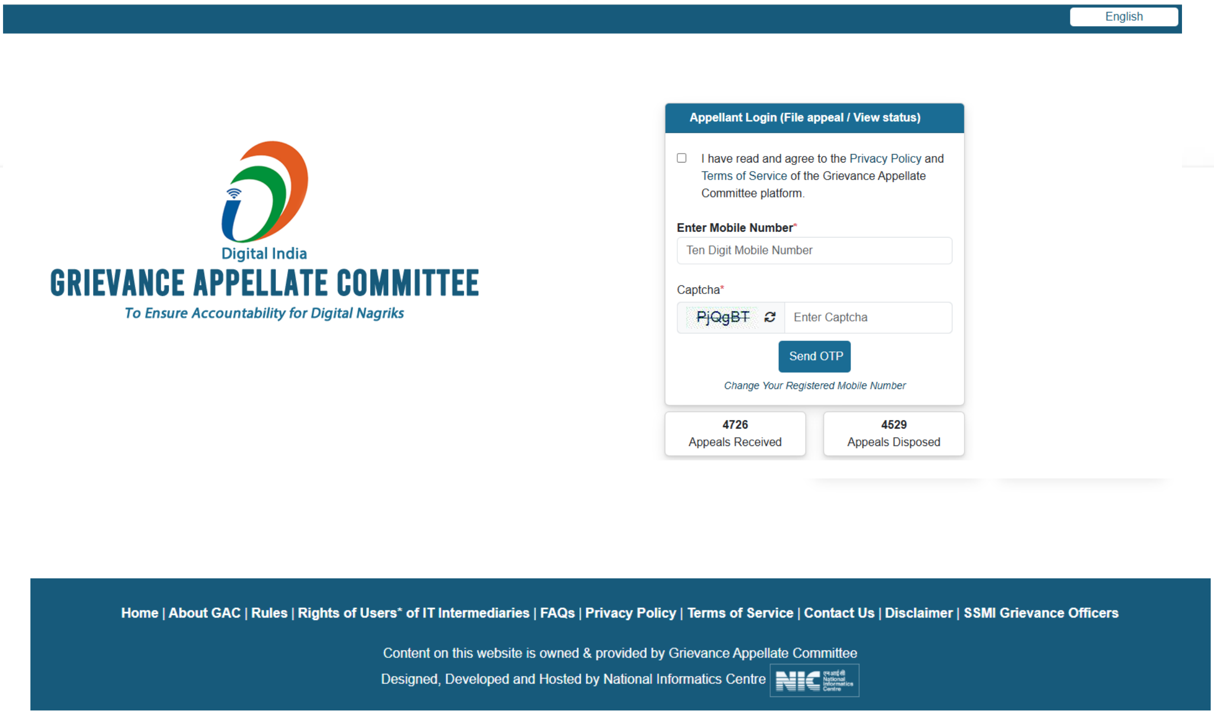

8. आयोजित प्रशिक्षण (वित्तीय वर्ष: 2025-26) # 3248	
प्रशिक्षित कर्मचारी (वित्तीय वर्ष: 2024-25)# 8279	
1. प्रशिक्षण का नाम: covid19cc, RATI, RT-PCR	
Covid19cc वेबसाइट, RATI मोबाइल ऐप, ऑनलाइन Covid19cc के RT-पीसी आर मोबाइल ऐप और PMCARES-OCMIS सिस्टम पर प्रशिक्षण	0
2. प्रशिक्षण का नाम: एच.पी.पी.एस.सी., सहयोग निदेशालय हिमाचल प्रदेश (सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण) और ई-विधान	
एच पी पी एस सी और सहयोग निदेशालय हिमाचल प्रदेश अधिकारी विशिष्ट मॉड्यूल पर सभी स्तरों के अधिकारियों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण दे रहे हैं	0
3. प्रशिक्षण का नाम: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर सामान्य जागरूकता	
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विषय पर सामान्य जागरूकता, जेसे कि, ईमेल, इंटरनेट, वायरलेस, एन.आई.सी. एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स पर प्रशिक्षण	214
4. प्रशिक्षण का नाम: राजस्व, राजस्व, ई-समाधान, ई-समीक्षा, वर्क्स एमआईएस (ई-आई पी एच) और स्कूल सुरक्षा एम आई एस	
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र के ई-हिमभूमि - ऑनलाइन चार्ज क्रिएशन, ई-समाधान सॉफ्टवेयर पर विभिन्न अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण	0
5. प्रशिक्षण का नाम: जिलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जागरूकता	
जिला स्तर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सम्बंधित एप्लीकेशन जेसे कि हॉट डाक, जीवन प्रमाण, पी.ए.ओ., वेतन, हिमरिस, चुनाव और कर्फ्यू के दौरान कोविडपास पर प्रशिक्षण	1476
6. प्रशिक्षण का नाम: ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली - यात्रा, छुट्टियां, पेंशन, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और मध्याहन भोजन - ए.आर.एम.एस.	
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली - मानव संपदा के विभिन्न मॉड्यूल पर महालेखाकार कार्यालय व अन्य राज्य कार्यालयों के अधिकारिओं को हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान की लैब में प्रशिक्षण	503
7. प्रशिक्षण का नाम: ट्रेजरी-ओ.एल.टी.आई.एस.	
ऑनलाइन ट्रेजरी सूचना प्रणाली और पी.ए.ओ. मॉड्यूल पर प्रशिक्षण	48
8. प्रशिक्षण का नाम: ई-प्रोक्योरमेंट और एन.जी.डी.आर.एस.	
विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ई-प्रोक्योरमेंट, ई-कल्याण, आई.आर.ए.डी. - एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस और एन.जी.डी.आर.एस. मॉड्यूल पर प्रशिक्षण	1007
9. प्रशिक्षण का नाम: डिजिटल साक्षरता और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	
ई-निर्वाचन क्षेत्र पर प्रशिक्षण-एवं-कार्यशालाओं का आयोजन व प्रबंध	0

* ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट में अद्यतनीकरण के उपरांत

9.0 नियोजित प्रमुख गतिविधियां

परियोजना का विवरण	नियोजित तारीख
कोविड-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली का पुनरुद्धार और आरटी-पीसीआर मोबाइल ऐप में संशोधन और राज्यों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण परिणाम प्रवेश मॉड्यूल, एन.ए.पी.एक्स ए.पी.आई को शामिल करना	पूर्ण, कोविड-19 डेटा हर 6 महीने में आई सी एम आर को हस्तांतरित किया जाएगा, डेटाबेस से गुमनामीकरण और शुद्धिकरण किया जाएगा
पर्यावरण चालान मोबाइल ऐप	कार्यान्वित
आधार के साथ रोजगार कार्यालय एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर उन्नयन, सी.एस.सी. एकीकरण (एल एम के) और निजी क्षेत्र के लिए इंटरफ़ेस	उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण - कार्य प्रगति पर है
Himachal.nic.in में ऑडियो वीडियो अनुभाग, स्टेट मूवी/ पी.पी.टी. अद्यतन।	सितंबर 2025 - कार्य प्रगति पर है
मानव संपदा के तहत कर्मचारियों द्वारा बिलों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण। ए सी आर मॉड्यूल में विभाग(ओं) के लिए विशेष नई सुविधाएँ	मार्च 2026
हि.प्र. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए पंजीकरण, शुल्क और लाभ संवितरण हेतु सॉफ्टवेयर समाधान	कार्यान्वयन के अंतर्गत
भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए “ऑक्सीकेयर” - ऑक्सीजन प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं सम्बंधित मोबाइल ऐप	मार्च 2026
निम्नलिखित क्षेत्रों में नई तकनीकों/टूल्स को अपनाना • AI आधारित दस्तावेज़ विश्लेषण-पी एस सी प्रमाणपत्र	अगस्त 2025 - कार्य प्रगति पर है
नई आवश्यकताओं के अनुसार, नई उन्नत सुविधाओं के साथ मध्याह्न भोजन स्वचालित रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सॉफ्टवेयर के रूप में अद्यतन करना	दिसम्बर 2023 (धन मुद्दा)
भूतपूर्व सैनिक पुनर्रोजगार प्रकोष्ठ सॉफ्टवेयर विकास (नई आवश्यकताएँ)	कार्यान्वयन के अंतर्गत
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग मोबाइल ऐप स्टोर पर सभी मोबाइल एप्लिकेशन की होस्टिंग	दिसम्बर 2025 कार्य प्रगति पर
एक नई पहल के रूप में एस ओ सी एम आई एस विकास	परीक्षणाधीन
ई-पी.डी.एस. - विक्रेता एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र समाधान में स्थानांतरित करना	दिसम्बर 2025 -पी ओ सी - कार्य प्रगति पर है
BOSE/ HP KVV पालमपुर: ई-वेतन और ई-पेंशन सॉफ्टवेयर, सुरक्षा ऑडिट और एस डी सी शिमला में क्लाउड स्थानांतरण, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निगम में प्रतिकृति	अगस्त 2025 - कार्यान्वयनाधीन
चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर-नई सुविधाएँ, , सुरक्षा ऑडिट और6क्लाउड शिफ्टिंग एसडीसी शिमला में	सितम्बर 2025- उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण कार्यान्वयनाधीन

मौजूदा सॉफ्टवेयर जैसे आई एफ एम एस, मानव संपदा, खोज निर्देशिकाएं, आई ओ एच आर एस, सामान्यीकृत आर एच आरक्षण प्रणाली में नई विशेषताएं	सितम्बर 2025
एन आई सी हिमाचल के सभी वेब और मोबाइल एप्लिकेशन का सुरक्षा ऑडिट। एन आईसी और एस डी सी क्लाउड सिस्टम के वी ए	नियमित गतिविधि
एच पी एस डी एम ए सॉफ्टवेयर - नई सुविधाएँ, पी एम एस - फिग्मा डिज़ाइन	अक्टूबर 2025 - कार्य प्रगति पर है
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग डीपीसी मॉड्यूल में परिवर्तन और अन्य अनुकूलन	समाप्त
प्रमाणीकरण के लिए स्थायी खाता संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से ई-के वाई सी के लिए जी.ए.सी. बैकएंड परिवर्तन और अतिरिक्त नई सुविधाएँ: • जी.ए.सी. सचिवालय के लिए प्रबंधन पैनल, मोबाइल ऐप • DBIM अनुपालन और ओपन सोर्स प्रौद्योगिकियों में माइग्रेशन	बैकएंड परिवर्तन - जी.ए.सी. के साथ लंबित अतिरिक्त सुविधाएँ - मार्च 2026
सभी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर में सुरक्षित पासवर्ड आवश्यक संशोधन	समाप्त
वेब अनुप्रयोगों का NGC 1.0 में स्थानांतरण/ एस डी सी शिमला	सितम्बर 2025 - कार्य प्रगति पर है
महत्वपूर्ण डेटा फ़ील्ड का एन्क्रिप्शन	समाप्त
होम गार्ड्स स्वयंसेवक एम आई एस	दिसंबर 2025
आर बी आई, ई-डिस्ट्रिक्ट, एन जी डी आर एस, किसान रजिस्ट्री (एग्री स्टैक), एचपी एपी पी पी के साथ भूमि रिकॉर्ड एकीकरण। आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग, जमाबंदी परिवर्तन, ऑनलाइन म्यूटेशन, अतिरिक्त एम आई एस रिपोर्ट	मार्च 2026
हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रोत्साहन योजना (एम आई एस), पशुपालन एवं डेयरी विभाग	अक्टूबर 2025

संपर्क

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, MEITY, भारत सरकार
हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र
हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला - 171002
फ़ोन: 0177-2624045
ई मेल: **sio-hp@nic.in**

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र National Informatics Centre

06-अक्टूबर-2025 को मुद्रित

Digital India Power To Empower